

विषय-सूची

पंचम खंड—विनिमय और व्यापार

पहला परिच्छेद—श्रीमन्

विनिमय और श्रीमन्—पदार्थों का बाजार—मार्ग और दृष्टि—
श्रीमन् और उत्पादन-व्यव—एकाधिकार में श्रीमन् ।

पृष्ठ २३१ से २४० तक

दूसरा परिच्छेद—देशी व्यापार

साहचर्य—व्यापार के भेद—देशी व्यापार—व्यापार के मार्ग और
साधन—रहकों—रेल—रेलों का चलनमान दशा के दोष—रेलवे-कमेटो
की रिपोर्ट—टाक और तार—नदियाँ और नहरें—गाज़ टोने की
उत्पत्ति का प्रभाव—देशी व्यापार के कुछ बंध—बंदरगाह और व्यापा-
रिक नगर—व्यापार की वृद्धि और स्वरूप—व्यापारियों का संगठन ।

पृष्ठ २४० से २४६ तक

तीसरा परिच्छेद—विदेशी व्यापार

साहचर्य—भारत का बाह्य व्यापार—परिस्थिति में परिवर्तन—
व्यापार की वृद्धि—आयात और निर्यात—व्यापार-वृद्धि का स्वरूप—
व्यापार वृद्धि का प्रभाव—व्यापार की बाड़ी—बाड़ी का सुगमन—
सरकारी हुंकार (Council bills)—सरकारी हुंदा का भव—
विनिमय की दर—रकमकी दर—एन्गर-रहोब सिद्धे—सोना की
दर में बदलाव—भारतीय ग्राहकों का हान—विदेशी ग्राहक—
भारतीय ग्राहकों के प्रति और सरकार ।

पृष्ठ २४६ से २०१ तक

निरचय—मज़दूरी और धावादी—आधुनिक मज़दूरी की वृद्धि—
 कम-से-कम मज़दूरी—अशांति के कारण—हड़ताल—अमजोबो-
 संघ—मद्रास के मज़दूर-संघ—बंबई के मज़दूर-संघ—अन्य स्थानों
 में मज़दूर-संघ—अंतर-राष्ट्रीय मज़दूर-कॉन्ग्रेस—सरकार और
 मज़दूर-दल—कॉन्ग्रेस का ध्यान—विशेष वृत्तव्य ।

पृष्ठ ३०६ से ३२४ तक

तीसरा परिच्छेद—सूद

सूद या व्याज—सूद पर रखा देने से लाभ—सूद के दो भेद—
 सूद की दर—पूँजी की मात्रा का प्रभाव—अणु-दाता—भारतवर्ष
 में सूद की दर—हिंदू-नियम—अणु-मस्तों की रक्षा ।

पृष्ठ ३२४ से ३३१ तक

चौथा परिच्छेद—मुनाफ़ा

मुनाफ़ा—मुनाफ़े के दो भेद—मुनाफ़े के म्यूनाधिब्य के कारण—
 कृषकों का मुनाफ़ा—कृषि-साहूकार का मुनाफ़ा—शिल्प-साहूकार
 का मुनाफ़ा—मध्यस्थ का मुनाफ़ा—आयात-निर्यात करनेवालों
 का मुनाफ़ा—फल-कारवानेवालों का मुनाफ़ा—पुस्तक-प्रकाशकों
 का मुनाफ़ा ।

पृष्ठ ३३१ से ३३८ तक

पाँचवाँ परिच्छेद—सामाजिक स्थिति

धन-विनिरण और समाज—धन का असमान विनिरण और उसका
 परिणाम—मज़दूरी से पूँजी और राज्य का अंगड़ा—समानता का
 उद्योग—भारतवर्ष की वर्ण-व्यवस्था—धन-विनिरण-व्यवस्था में सुधार ।

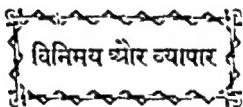
पृष्ठ ३३८ से ३४२ तक

सातवाँ खंड—भारतीय राजस्य

पहला परिच्छेद—स्थानीय राजस्य

प्राद्वयन—युनिसिपैलिटियों और कॉर्पोरेशनों के काम—युनि-

पंचम खंड



विनिमय और व्यापार

पहला परिच्छेद

क्रीमत

विनिमय और क्रीमत—विनिमय की आवश्यकता इस पुस्तक के प्रथम भाग में बतलाई जा चुकी है। आधुनिक संसार में विनिमय का कार्य तभी होता है, जब पदार्थों की क्रीमत रूप-पैसे (Money) के रूप में निरिचन हो जाती है। रूप-पैसे आदि का वर्णन चौथे खंड में कर चुके हैं। अब क्रीमत के संबंध में विचार करना है। किसी वस्तु की क्रीमत का उसके बाज़ार से घनिष्ठ संबंध होता है। अतः इस परिच्छेद में पहले बाज़ार की ही विवेचना करते हैं।

पदार्थों का बाज़ार—अर्थ-शास्त्र में किसी पदार्थ के बाज़ार से उस स्थान का ही अभिप्राय नहीं होता, जिसे हम अपने साधारण बोल-चाल में बाज़ार या मंडी कहते हैं, परन्तु उस सारे क्षेत्र से होता है, जिसमें वेचने और खरीदनेवालों का ऐसा संबंध हो कि उस क्षेत्र में उस पदार्थ की क्रीमत समान होने की प्रवृत्ति हो। यदि किसी वस्तु का व्यापार संसार के भिन्न-भिन्न देशों में सुगमता-पूर्वक और अल्प व्यय से होता हो, तो उसका बाज़ार तमाम दुनिया हो सकती है। इसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। बाज़ार-भर में किसी एक वस्तु की क्रीमत समान होने की श्राव्यवृत्ति (Tendency) रहती है। परंतु क्रीमत बिल्कुल समान नहीं होने पाती; क्योंकि भिन्न-भिन्न स्थानों में चीज़ों के ले जाने में अर्थ पड़ता है। फ़ैटम, खुंशो या अन्य व्यापारिक कर भी ले ही जाने के अर्थ में शामिल हैं।

(१) उनके यथेष्ट वर्णन की कठिनाई ।

(२) उनका वजन और स्थान का परिमाण ।

सबसे कम विस्तृत बाजार भूमि का है । मकानों अथवा व्यक्तिगत रुचि के अनुसार बने हुए सामान की भी प्रायः ऐसी ही दशा है ।

माँग और पूर्ति—चीजों का मूल्य तभी लगता है, जब (क) उनमें लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करने के कुछ गुण हों, और (ख) वे ऐसी हों कि प्रचुर परिमाण में यों ही न मिलें ।

मिहनत से सब चीजों की क्रीमत बढ़ती है, पर मिहनत ही क्रीमत का एक-मात्र कारण नहीं । इसका प्रधान कारण चीजों की प्राप्त करने की लोक-रुचि, और उनके द्वारा लोगों की आवश्यकताएँ पूरी होने की उनकी योग्यता है । ऐसा न होता, तो हीरे और मानूखी पत्थर पर बराबर मिहनत करने के बाद दोनों की क्रीमत भी बराबर हो जाती ।

वस्तुओं की क्रीमत घटती-बढ़ती रहती है । यह उनकी माँग और पूर्ति (Supply) के अर्थान है । माँग की अपेक्षा पूर्ति कम होने पर वस्तु के खरीददार बढ़ा-ऊपरी करने लगते हैं । जिसे जो चीज दरकार होती है, वह वही चाहता है कि चीरों को वह मिले या न मिले, पर मुझे मिला जाय । इस बढ़ा-ऊपरी के कारण चीज की क्रीमत भी बढ़ जाती है—वह मईगी हो जाती है । इसी तरह वस्तु की माँग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होने से उसके बेचनेवाले बढ़ा-ऊपरी करते हैं, और माल की क्रीमत गिर जाती है । इससे यह सिद्ध होता है कि अधिक पूर्ति या कम माँग होने पर क्रीमत कम होती है, और पूर्ति के कम या माँग के अधिक होने पर वह अधिक हो जाती है ।

किसी वस्तु की क्रीमत वही होती है, जिस पर जितनी उसकी माँग हो, और उतनी ही उसी समय उसकी पूर्ति भी हो ।

रहता है। कभी कुछ इधर हो जाता है, तो कभी उधर। भिन्न-भिन्न व्यवसायों में, अपना प्रभाव ढालने में, उत्पादन-व्यय को कभी तो अधिक और कभी कम समय लगता है। फलों के काम को ही लीजिए। अब पृष्ठ खगाए जा चुके हैं, तो मासिक प्रमल के मौजे पर उनकी अच्छी-बे-अच्छी प्रीमन लेने की कोशिश करना है। एक व्यवसाय में जारी हुई पूँजी को किसी दूसरी जगह खगाने का विचार तुरंत नहीं किया जाता। यदि फल के काम में उत्पादन-व्यय न निकला, तो वह अगली प्रमल में फल के पृष्ठों को कम करके, उसमें लगाई गई पूँजी को किसी दूसरी वस्तु में खगाने का विचार करेगा। परंतु यदि लाभ अच्छा हुआ, तो वह अगली प्रमल में वैसे ही कुछ अधिक लगावेगा, और उसकी देखा-देखी दूसरे भी उसी कार्य में अधिक पूँजी लगावेंगे। इस प्रकार यद्यपि कृषि-जग्य पदार्थों की प्रीमन उसकी प्रमल पर ही निर्भर रहती है, तथापि उत्पादन-व्यय अवरय निकलना चाहिए। अन्यथा, कारण न की जा सकेगी।

मान से निकलनेवाले पदार्थ तथा अन्न ऐसी चीजें हैं, जिनकी पूर्ति कुछ समय के बाद अवरय बढ़ाई जा सकती है। इनका निर्र निर्दिष्ट करने में उत्पादन-व्यय का प्रभाव पड़ता है। उसका दरवाला रखकर ही माँग तथा पूर्ति की समता से ऐसी चीजों का निर्र निर्दिष्ट होता है। उत्पादन में अधिक रुकने से इनकी पूर्ति बढ़ सकती है। पर जित्त अनुपात से रुकें बढ़ता है, उसी अनुपात से पूर्ति बढ़ती है। यहाँ 'अमागत इति-नियम' लागू हो जाता है।

बाजों की मदद से जो चीजें तैयार होती हैं, उनकी पूर्ति बहुत कुछ आसानी से बढ़ाई जा सकती है। ऐसी चीजों की पूर्ति ईसे-ईसे बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे उनका जो मदद उत्पादन-व्यय कम होता जाता है। ऐसी चीजों का निर्र, माँग तथा पूर्ति की समता से, उत्पादन-व्यय के कुछ इधर या उधर निर्दिष्ट होता है।

तक बढ़ाता है, जहाँ तक वह इतनी मात्रा में बिक सके कि उसे अधिक-से-अधिक लाभ हो। इस सीमा के बाद वस्तु की कीमत बढ़ाने से उसे उतना लाभ न होगा।

उदाहरण के लिये कल्पना कीजिए कि किसी चीज़ की क्रोमन दो आने हैं, और उसकी माँग १०,००० तथा उत्पादन-व्यय एक आना प्री-अदद है, तो एकाधिकारी को १०,००० आने का मुनाफ़ा होगा। अब मान लीजिए कि कीमत तीन आने करने पर उसकी माँग ८,००० हो रह जाय, और इसलिये अदद कम तैयार किए जाने की वजह से यदि उसका उत्पादन-व्यय एक आने प्री-अदद से बढ़कर सवा आना हो जाय, तो उसका मुनाफ़ा १४००० आने होगा। पूरा हिसाब नक्शे में इस प्रकार दिखाया जाता है—

कीमत प्री-अदद (आने)	माँग	कुल आय (आने)	प्री-अदद उत्पादन- व्यय (आने)	कुल उत्पा- दन-व्यय (आने)	एकाधिकारी का मुनाफ़ा (आने)
२	१०,०००	२०,०००	१	१०,०००	१०,०००
३	८,०००	२४,०००	१.२५	१०,०००	१४,०००
४	६,२००	२४,८००	१.५	९,२००	१५,६००
५	४,६००	२३,०००	१.७५	८,०५०	१४,९५०
६	३,५००	२१,०००	२	७,०००	१४,०००
७	२,०००	१४,०००	२.२५	४,५००	९,५००
८	१,२००	८,६००	२.५०	३,०००	५,६००

इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि चार आने कीमत कर देने पर उसे सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। कीमत और अधिक बढ़ाने पर उसका मुनाफ़ा घटने लगेगा। इसलिये वह उसकी कीमत चार आने रखेगा।

व्यापार का सिद्धांत यह है कि दोनों पक्ष को लाभ हो । जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं या कम ज़रूरत है, वही दी जाती और अधिक ज़रूरत की चीज़ ली जाती है । व्यापार से यद्यपि कोई मर्द चीज़ नहीं पैदा होती, मो भी पदार्थों की उपयोगिता बढ़ जाती है । अतः अर्थ-शास्त्र की दृष्टि से यह एक उत्पादक कार्य है ।

व्यापार के भेद—व्यापार दो तरह का होता है—देशी (Inland) और विदेशी (Foreign) । देशी व्यापार देश की सीमा के भीतर का व्यापार है । विदेश से आनेवाले और विदेश को जानेवाले भाज के व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं ।

देशी व्यापार

पहले देशी व्यापार का वर्णन किया जाता है । इसमें निम्न-लिखित प्रकार के कार्य होते हैं—

(क) देश में उत्पन्न या निर्यात किए गए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना या विदेश भेजने के लिये बंदे-बंदे दूर गाहों पर ले जाना ।

(ख) विदेशों से देश के बंदरगाहों में आए हुए भाज को देश भर में फैलाना ।

(ग) सराफ़ी, व्यापार, दुकानें और बीसे आदि के काम । आज-कल मर्द और और का भी व्यापार से हुनना पड़ता है । मरवेध हो गया है कि कुछ लोग हुनमें और व्यापार से कोई भेद नहीं समझते । उरर जिस व्यवसाय का उद्देश्य है, उररें बौदहर ओ बरद-दिवर बंदर तेज़ी-मदी होने की संभावना पर, ज़रा होने की आशा से, किए जाता है, उसे सरा (Speculation) कहते हैं । हुमने केके तथा एरीरे गए भाज को देना-लेना होता है । हुसके अनिरेर ओ सीर बंदुमार लाभ होने की आशा से, हुसिदन से अधिक, किए जाता है,

का प्रसार है। जब से रेल की लाइनें खुलीं, तब से देश-व्यापी सड़कों की आवश्यकता कम समझी जाने लगी। सरकार ने अब सड़कों का काम अधिकांश में जिले के बोर्ड या म्युनिसिपैलिटियों के हाथ में दे दिया है। इनका ध्यान अपने ही इलाके-भर में रहता है, बाहर नहीं। जिले के चंद्र भी सदर मुकाम और सब-डिवीजन के केंद्र के बीच की, अक्सरों के दूरे की सुविधा बनाए रखने के लिये, सड़कें तो अच्छी हालत में रखी जाती हैं, किंतु दूसरे रास्तों पर कृपा-दृष्टि नहीं की जाती। उचित तो यह है कि प्रधान-प्रधान मंडियों को केंद्र बनाकर इलाके-भर में लंबी, चौड़ी और पक्की सड़कें बनवा दी जायें, और उनके द्वारा मंडियों से गाँव-गाँव का संबंध करा दिया जाय, एवं बीच की नदियों पर पुल बांध दिए जायें। इससे देशी व्यापार की बहुत वृद्धि होगी। किंतु ऐसा नहीं है।

रेल—आधुनिक व्यापार-वृद्धि में रेलों से बड़ी सहायता मिल रही है। इनका काम यहाँ सन् १८५६ में आरंभ हुआ।

भारतवर्ष में ३१ मार्च, १९२६ को कुल ३८,२७० मील रेल थी। इसमें से १६,४१४ मील भारत-सरकार की निज की संपत्ति थी। इसका वह स्वयं प्रबंध करती है। शेष में ११,८५६ मील सरकार की संपत्ति तो थी, पर उसका प्रबंध कंपनियों के हाथ में है। शेष रेलों में कुछ डिस्ट्रिक्ट-बोर्डों या देशी राज्यों की थीं। प्रास कंपनियों की रेलें बहुत कम हैं। प्रबंधकारिणी कंपनियाँ, शर्तनामे के अनुसार, कुछ मुनाफ़ा पाती हैं। बाक़ी सब मुनाफ़ा सरकार को मिलता है।

रेलें चार तरह की हैं—

- (१) स्टैंडर्ड माप की—अर्थात् साढ़े पाँच फ़ीट चौड़ी
- (२) मीटर माप की—अर्थात् ३-२८ फ़ीट चौड़ी
- (३) छोटे माप की—अर्थात् ढाई फ़ीट चौड़ी
- (४) छोटी जाइन—अर्थात् दो फ़ीट चौड़ी

रुई पंजाब से मुरत भेजनी होती थी, तो पहले मैं बंबई को रवाना करता था, और फिर बंबई से लौटाकर मुरत को ; क्योंकि पंजाब से सीधे मुरत भेजने में बहुत अधिक प्रबं लगता था ।

(४) कच्चे माल के निर्यात को जैसी उत्तेजना दी जाती है, वैसी तैयार माल के निर्यात को नहीं । उदाहरणार्थ, तेलहन की अपेक्षा तेल बाहर भेजने में किराया बहुत अधिक देना पड़ता है ।

(५) रेलवे-कंपनियों के स्वार्थ अलग-अलग हैं, और प्रबंध भी पृथक् पृथक् । इसलिये वे सब अपना-अपना लाभ देखती हैं, देश के लाभ का उन्हें ध्यान नहीं । यदि सबका स्वार्थ और प्रबंध एक ही हो, तो व्यापारियों की असुविधाएँ कम हो जायें ।

(६) लगभग ६६ ग्री-सैकड़े यात्री तीसरे दर्जे में सफर करते हैं । उन्हीं में अधिक आय भी होती है । परन्तु विदेशी कंपनियाँ और सरकार उनके अपार कष्टों की कुछ परवा नहीं करती ।

(७) जब रेलें खुलीं, तो बड़े-बड़े शहरों और व्यापार की मंडियों से होती हुई गई । उस समय देश के भीतरी भागों का ध्यान नहीं रखा गया । मद्रास और मद्रियाँ के पुर्जों का भी सुधार नहीं हुआ । पीछे प्रांथ(शाखा)-लाइनें खुलने लगीं । पर उनमें बड़े-बड़े कृषि नहीं हुई । इसलिये सब धंधे घने शहरों में ही इकट्ठे होते गए ।

(८) रेलों की माप भिन्न-भिन्न है । इसलिये जब माल को एक लाइन से उतारकर दूसरी लाइन पर लादना पड़ता है, तो किराए में व्यर्थ ही वृद्धि हो जाती है । साथ ही टूटने और चोरी जाने की जोखिम भी बढ़ जाती है ।

(९) इस देश में रेलवे-लाइनें क्यों से खुली हुई हैं । किन्तु रेलों का अधिकांश सामान अभी विदेशों ही से आता है । उचित तो यह है कि रेलों के डिब्बे आदि सब सामान यहाँ तैयार कराया जाय, और उसके खिचे कौटों ररवा विदेश न भेजा जाय ।

रेलवे-प्रबंध के संबंध में कमेटी के सदस्यों में मत-भेद हो गया है। यह तो सब सदस्य स्वीकार करते हैं कि इंग्लैंड की कंपनियों द्वारा प्रबंध होना अनुचित है। परंतु पाँच का मत है कि जब कंपनियों के ढेकों की अवधि • समाप्त हो जाय, तब सरकार उनका प्रबंध अपने हाथ में ले ले। अन्य पाँच सदस्यों का यह कहना है कि अवधि समाप्त होने पर सरकार रेलों का प्रबंध विदेशी कंपनियों से छुड़ाकर नई भारतीय कंपनियों को सौंप दे। यदि यह प्रबंध सफल हो, तो आज-कल जिन रेलों का प्रबंध सरकार स्वयं करती है, उनको भी भारतीय कंपनियों के हाथ में सौंप देने के प्रश्न पर विचार किया जाय।

गत प्रशस्ती, सन् १९१३ ई० में इस विषय पर यहाँ भारतीय व्यवस्थापक सभा में प्रबुध बहस हुई। जहाँ को यह प्रश्नाव स्वीकृत हुआ कि इंस्ट्रुमेंट्स और जी० आई० पी०-रेलों को सरकार, अवधि के बाद, कंपनियों के हाथ से निकालकर अपने प्रबंध में ले ले। इस निश्चय के अनुसार ये रेलें सन् १९१५ ई० में सरकारी प्रबंध में ले ली गईं।

जिस समय तक सरकार भारतीय जनता के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी नहीं है, उस समय तक रेलों का प्रबंध उसके द्वारा किए जाने में हमें कुछ अधिक लाभ नहीं मालूम होता। अतः रेलों का प्रबंध भारतीय कंपनियों के हाथों में होना उचित है।

• मुख्य-मुख्य रेलवे कंपनियों के ढेकों की अवधि अंतर्गत में ली गई

प्रस्ताव और महान् ग्रहण-
महान् इतिहास-लेख, सन्
१९०१। बंगाल-नामपुर-

काल के बहुत-से बंदरगाह अब व्यापार के लिये उपयोगी नहीं रहे हैं।

देश में कुछ नगर व्यापारिक केंद्र हैं। वहाँ से माल भिन्न-भिन्न स्थानों में पहुँचना है। संयुक्तप्रान्त में कानपुर और लखनऊ, पंजाब में लाहौर, दिल्ली-प्रान्त में दिल्ली और मध्य-प्रान्त में भागपुर प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं।

व्यापार की वृद्धि और स्वरूप—जिस समय इंग्लैंड इटाली-फ्रान्स ने भारत का राज्य-भार लिखा, उस समय भारत के देशी व्यापार की दशा शोचनीय थी। मरकें पराब थी, 'राजनीतिक अंधल-पुधल और अशांति के कारण खोरी तथा टर्फी का बहुत दर था। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने गाँवों में ही पैदा कर लेते, बना और बेच लेते थे। यदि कुछ बची रही, तो वह घास-घास के 'हाटों' या 'मेलों' में पूरी कर ली जाती थी। बाहरी दुनिया से उनका बहुत कम संबंध रहता था।

शांति स्थापित होने, खोरी और टर्फी का भय दूर होने तथा मरकें और रेल की छाहों से व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। साथ ही पुराने बाजारों और मंडियों की प्रधानता जाती रही है। रेलवे छाहों के किनारे नए नगर बस गए। अब बंदरगाहों की उन्नति हो रही है, क्योंकि देश का माल यहाँ से विदेशों को रवाना होता है, और विदेशी माल यहाँ से आकर देश-भर में फैल जाता है।

हम व्यापार की दशाएँ बड़ी-बड़ी राजनीति-कारियों के हाथ में हैं। हमारे प्रधान कारिगार तो प्रायः विदेशी हैं, लेकिन प्रधान कारिगारों यहाँ के बड़े-बड़े बंदरगाहों में हैं। कभी-कभी मुद्रास्मिद्ध

भारत के व्यापार का सत्र बंदरगाहों की ओर फिरा हुआ है। देहातों का बचा हुआ माल रेल-किनारे के बाजारों में पहुँचना है। वहाँ से वह या तो दूसरे बाजारों में या बंदरगाहों पर जाता है। बंदरगाहों में आने के दो अभिप्राय हैं—एक तो जहाज़ों द्वारा उसका विदेश जाना या एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह को रवाना होना। दूसरे, उन बंदरगाहों की मिसों में उससे तैयार माल बनना। इस प्रकार देशी व्यापार का, बहुत धरों में, इन्हीं बंदरगाहों से संबंध है।

व्यापारियों का संगठन—अपने हितों और स्वार्थों की रक्षा के लिये व्यापारियों को भी संगठित होने की आवश्यकता है। योरपियन व्यापारियों ने संगठन का महत्त्व जानकर अपनी संस्थाएँ—चेंबर आफ् कामर्स (Chamber of Commerce) और ट्रेड-एसोसिएशन (Trade Association)—कायम कर रखी हैं। भारतीय व्यापारियों ने भी जहाँ-तहाँ अपनी संस्थाएँ स्थापित की हैं; परंतु उनमें बड़े शक्ति नहीं है। इसलिये उन्हें रेलवे-कंपनियों और माल भेजने का लाइसेंस देनेवाले अधिकारियों के हाथों तरह-तरह से अन्याय और कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तथापि भारतीय व्यापारियों का संगठन इस कार्य को आगे अग्रसर बना सकता है।

अस्तु, भारतवर्ष में एक ऐसी वैदेशीय संस्था की बड़ी आवश्यकता है, जो अपनी प्रांतीय शाखाओं द्वारा समस्त भारतवर्ष के उद्योग-धर्मों की वैसी ही रक्षा और उत्थिति करे, जैसी अन्य देशों की संस्थाएँ अपने-अपने देश में करती हैं।

(७० लाख रुपए) का सोना और चाँदी रोम में प्रतिवर्ष भारतवर्ष को जाता है ।

आठवीं शताब्दी में क्रमशः तुर्कों का बल बढ़ा, यहाँ तक कि सन् १४५३ ई० में कुस्तुनमुनिया उनके हाथ आ गया । फिर धीरे-धीरे भूमध्य-सागर और मिस्र पर भी इनका अधिकार हो जाने के कारण, योरपवालों को इस रास्ते में व्यापार करके मनमाना लाभ उठाने में बाधा पड़ने लगी । अंततः सन् १४८८ ई० में पुर्तगालवालों ने “उत्तम आशा”-अंतरीप (Cape of Good Hope) के रास्ते, आफ्रिका के गिर्द होकर, भारतवर्ष आने का रास्ता ढूँढ़ निकाला, और पूर्वी व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर लिया । धीरे-धीरे हालैंड, ईंगलैंड और फ्रांसवालों ने भी अपनी-अपनी कंपनियाँ खोलीं । इन सबमें खूब लड़ाई-झगड़े होते रहे । अंत को अँगरेजों की जीत हुई । उन दिनों सड़कें, बंदरगाह, माल ढोने के साधन आदि उन्नत अवस्था में नहीं थे । सफ़र लंबा था, खर्च बहुत पड़ता था । तो भी भारत का व्यापार (अधिकांश शिल्पीय) कम लाभदायक नहीं था । सन् १६८२ ई० में ईस्ट इंडिया-कंपनी ने १५० प्रति-सैकड़े का मुनाफ़ा बाँटा था ।

परिस्थिति में परिवर्तन—मध्य-काल के अंधकार-युग में इस देश के आंतरिक कलह, कूट और आलस्य ने क्रमशः इसके आर्थिक महत्त्व का नाश कर दिया । तथापि मुग़ल-शासन के अधिकांश समय तक यहाँ के कृषक और कारीगर सुख ही की नोंद सोते रहे । बादशाहों की सुरक्षित तथा शांतिनी के कारण इस देश का कला-कौशल और शिल्प विदेशों के लिये आदर्श बना रहा । सत्रहवीं नहीं, अठारहवीं शताब्दी में भी इस देश के बने हुए उनी, सूती और रेशमी वस्त्रों तथा खाँद, रंग, भस्माले आदि अन्य द्रव्यों के लिये सारा योरप खालायित रहता था ।

विदेशी व्यापार

२५६

सन्	वापिक श्रीसप्त आयान (करोड़ रुपया)	वापिक श्रीसप्त निर्यात (करोड़ रुपया)	कुल व्यापार (वापिक श्रीसप्त)
१८३५-४४	६००२	१३०४	२३०४६
१८४५-५४	१४००६	१८००६	३२०८२
१८५५-६४	३००४३	६६०४४	९६०८७
१८६५-७४	४४०७६	२६०६१	१०००४७
१८७५-८४	६००५४	७४०५४	१३०००६
१८८५-९४	८३०२७	१०२०६६	१८५०८३
१८९५-१९०४	१०५०७१	१३००६६	२३५०८७
१९०५-१९१४	१४३०६२	१७४०२६	३१८०१८
१९१५-१९२४	१४३०७६	१७४०३१	३१७००७
१९२५-१९३४	१६१०८८	१८२०७५	३४३०६३
१९३५-१९४४	१७८०६३	१८२०६३	३६०१२६
१९४५-१९५४	१८१०५३	१८६०४६	३६७०९९
१९५५-१९६४	१९००१७	१८४०३६	३७४०५३
१९६५-१९७४	१७३०४४	२१७००६	३९००५०
१९७५-१९८४	१८७०५३	२३८०३६	४२५०८९
१९८५-१९९४	२०५०४६	२५६०८५	४६१०३१
१९९५-२००४	२३४०७५	२५६०८५	४९००८५
२००५-२०१४	२६६०७५	२८००४७	५४६०२१
२०१५-२०२४	२८००१२	२८००७६	५६००८९
२०२५-२०३४	२८८०७०	२८३०७८	५७१०४८
२०३५-२०४४	२९६०१२	२८२०४५	५७८०५७
२०४५-२०५४	२८६०६३	२६४०३३	५५००२६
२०५५-२०६४	२८६०६४	२४६०४४	५३२०३८
२०६५-२०७४	२३८०६८	२३४०३०	४७२०९८
२०७५-२०८४	२६६०३५	२४६०४४	५१२०७९
२०८५-२०९४	२३२०७१	३१४०३१	५४६००२
२०९५-२१०४	२२७०६३	३६१०६७	५८८०३०

उपर्युक्त तालिका में सरकार के स्टोर्स धान के सामान का मुख्य भाग सम्मिलित है।

उपर्युक्त कोष्ठक में आयात की कीमत, कुल आयात की कीमत से पुनर्निर्यात की कीमत घटाकर, रक्काई गई है।

साधारणतः तैयार माल की कीमत हमारे आयात की कीमत की सत्तर-अस्सी फी-सदी होती है, जिसमें से लगभग ३० फी-सदी रई के कपड़े तथा सूत की, ८ फी-सदी लोहे के सामान की, ६-७ फी-सदी विविध चीजों की, ४ फी-सदी रेल के सामान की, ३ फी-सदी धातु इत्यादि की चीजों की और शेष अन्य विविध पदार्थों की होती है। तैयार मालों को छोड़कर चीनी ही अधिक कीमत की चीनी है।

हमारे निर्यात की कीमत में ४०-५० फी-सदी कच्चे पदार्थों, रई, जूट, तेलहन और चमड़े की कीमत होती है। तैयार माल (प्रधानतः जूट तथा कुछ रई के वस्त्र इत्यादि) की कीमत लगभग २५ और औद्योगिक तथा पेष पदार्थों एवं लकड़ी की कीमत लगभग ३० फी-सदी होती है।

साधारणतः लाख पदार्थों में बहुत-सा खाल और गेहूँ बाहर भेजा जाता है। निर्यात-खाल की मात्रा कुछ प्रमत्त में सैकड़े पीछे ० और गेहूँ की सैकड़े पीछे १० होती है। जौ भी काफी मात्रा में बाहर जाता है। दूसरे कुछ चीजों से कपास की प्रसख का लगभग आधा भाग बाहर चला जाता है। भिन्न-भिन्न तेलहनों के निर्यात का अनुपात भिन्न-भिन्न है। उदाहरण-स्वरूप तिल तो प्रधानतः बाहर भेजने के लिये ही पैदा किया जाता है। किन्तु भूँगपत्ती, रई और चमड़ा की कुछ प्रसख का प्रायः ९० फी-सदी से अधिक हिस्सा बाहर गते जाता। जूट के उद्योग-पथों की यहाँ उन्नति होती जाने के कारण कच्चे जूट का बाहर भेजा जाना कम हो रहा है। तथापि वह अब भी बड़ी मात्रा में, कुछ प्रसख का लगभग आर्द्धांश तक, बाहर भेजा जाता है। संसार के बाजारों में जिनकी का बिक्री है, उसमें ४० फी सैकड़ा भारत में ही उत्पन्न होती है।

उपर्युक्त कोष्टक में आयात की कीमत, कुल आयात की कीमत से पुनर्निर्यात की कीमत घटाकर, रक्की गई है।

साधारणतः तैयार माल की कीमत हमारे आयात की कीमत की सत्तर-अस्सी फी-सदी होती है, जिसमें से खगमग ३० फी-सदी रई के कपड़े तथा सूत की, ८ फी-सदी लोहे के सामान की, ६-७ फी-सदी विविध धातुओं की, ४ फी-सदी रेल के सामान की, ३ फी-सदी धातु इत्यादि की चीजों की और शेष अन्य विविध पदार्थों की होती है। तैयार मालों को छोड़कर चीनी ही अधिक कीमत की आती है।

हमारे निर्यात की कीमत में ४०-५० फी-सदी कच्चे पदार्थों, रई, जूट, तेलहन और चमड़े की कीमत होती है। तैयार माल (प्रधानतः जूट तथा कुछ रई के वस्त्र इत्यादि) की कीमत लगभग २५ और भोज्य तथा पेय पदार्थों एवं तंबाकू की कीमत लगभग ३० फी-सदी होती है।

साधारणतः खाद्य पदार्थों में बहुत-सा चावल और गेहूँ बाहर भेजा जाता है। निर्यात-चावल की मात्रा कुल क्रसल में सैकड़े पीछे ७ और गेहूँ की सैकड़े पीछे १० होती है। जौ भी काफ़ी मात्रा में बाहर जाता है। इधर कुछ वर्षों से कपास की क्रसल का लगभग आधा भाग बाहर चला जाता है। भिन्न-भिन्न तेलहनों के निर्यात का अनुपात भिन्न-भिन्न है। उदाहरण-स्वरूप तिल तो प्रधानतः बाहर भेजने के लिये ही पैदा किया जाता है। किन्तु भूँगफली, राई और अलसी की कुल क्रसल का प्रायः २० फी-सदी से अधिक हिस्सा बाहर नहीं जाता। जूट के उद्योग-धंधों की यहाँ उन्नति होती जाने के कारण कच्चे जूट का बाहर भेजा जाना कम हो रहा है; तथापि वह अब भी बड़ी मात्रा में, कुल क्रसल का लगभग अर्द्ध-श तक, बाहर भेजा जाता है। संसार के बाजारों में जितनी चा विकती है, उसमें ४० फी सैकड़ा भारत में ही उत्पन्न होती है।

जा रहा है। अब हम यह बतलायेंगे कि हम व्यापार-वृद्धि का म्यन्त्र क्या है।

(१) पहले भारतवर्ष में खाई, नील, दुशाले, मलमल आदि तैयार माल विदेशों को जाता था; किन्तु अब अब या रुई, गन, तेलहन आदि कच्चे माल का, जिसकी विदेशी कारखानों की आवश्यकता है, निर्यात बढ़ रहा है। विदेशों से आनेवाला माल प्रायः वही है, जो पहले यहाँ से बाहर जाता था। अथवा मोटरगाड़ी, साइकिल आदि नई वस्तुएँ हैं।

(२) भारतवर्ष का निर्यात आयात की अपेक्षा बहुत अधिक कीमत का होता है।

(३) हमारे निर्यात और आयात की कीमत में जो अंतर होता है, उसकी अपेक्षा हमारे व्यापार की बाकी की रकम बहुत कम होती है। (इसका कारण आगे बतलाया जायगा।) यह व्यापार की बाकी कीमती धानुओं के स्वरूप में आती है, जिसकी मात्रा बहुत मालूम करने पर भी भारतीय जन-संख्या की दृष्टि से बहुत कम होती है।

(४) हमारे आयात का लगभग ६५ प्रति-सदी हिस्सा इंग्लैंड से आता है, जो हमारे निर्यात का केवल २५ प्रति-सदी हिस्सा ही लेता है।

(५) व्यापार का नक्का, जहाज़ का किराया तथा बीमे और भाहूकारी आदि की आसानी अधिकतर योरपियनों को मिलती है।

व्यापार वृद्धि का प्रभाव—विशेषतः गन पचास वर्षों में विदेशी माल अधिकाधिक मँगाने और विनिमय में उससे भी अधिक कच्चे माल की निकासी करते रहने का परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता को हम बात की और ज्यादा जरूरत पड़ती जा रही है कि वह खेती पर अपना निर्वाह करे।

मेंगते । हमसे हमारी चाक्री इंग्लैंड के व्यापारियों के नाम निकलती है । परन्तु होम-घार्जेज आदि के लिये हमें प्रतिवर्ष बहुत-सा रुपया भारत-मंत्री को देना पड़ता है । भारत-मंत्री, इंग्लैंड में, वहाँ के व्यापारियों के हाथ भारत-सरकार के नाम की हुंडियों या कौंसिल-बिल बेचकर, हमारा रुपया जमा कर लेते हैं । जो लोग ये हुंडियाँ खरीदते हैं, वे उन्हें यहाँ भेज देते हैं, और यहाँ के व्यापारी सरकार या बैंकों से हुंडियों का रुपया समूल कर लेते हैं । इस प्रकार इंग्लैंड के व्यापारी भारतीय व्यापारियों को और भारत-सरकार भारत-मंत्री को बहुत सा नकदी भेजने की अनुविधा और जोखिम से बच जाती है ।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि क्रसल चर्खा न होने आदि के कारण जब यहाँ से इंग्लैंड को माल कम जाता है, तो हमें रुपया इंग्लैंड को देना पड़ता है । इस दशा में भारत-सरकार हुंडियाँ बेचती है और व्यापारियों से रुपया लेती है । भारतीय व्यापारी भारत-सरकार से हुंडी खरीदकर, उन्हें इंग्लैंड के व्यापारियों के पास भेज देते हैं, और इंग्लैंड के व्यापारी उन हुंडियों के बदले भारत-मंत्री ॥ सावरेन (पौंड) ले लेते हैं ।

भारत-मंत्री और भारत-सरकार, जल्दी भुगतान करने के लिये, तार द्वारा भी व्यापारियों का काम कर देती है । इससे खर्च कुछ अधिक होता है ।

सरकारी हुंडी का भाव—जब विलायत के व्यापारियों को यहाँ अधिक भुगतान करना होता है, तो सरकारी हुंडी की माँग बढ़ जाती है, अर्थात् एंगरेज़ी-सिक्के के हिसाब से भारतीय सिक्के का मोल बढ़ जाता है । या यों कह सकते हैं कि हमारे विनिमय का भाव बढ़ जाता है । यह भाव इसी क्रम में बढ़ सकता है कि इंग्लैंड के व्यापारियों को नकद रुपए भेजने की अपेक्षा हुंडी द्वारा भेजने

संबंधी नियम जान लेना आवश्यक है । हिसाब लगाने से मालूम होना है कि पीट की फ्रैंक में टक्याली दर २५-२२ है । हमी प्रकार अन्य मुख्य-मुख्य देशों की टक्याली दर नीचे-लिखे अनुसार है—

इंगलैंड और जर्मनी	एक पीट=२०.४३ मार्क
" " आस्ट्रिया	एक पीट= २४.०२ फ्राउन
" " अमेरिका	एक पीट= ४.८० डॉलर
" " रूस	एक पीट=२४.५० रुबल

उपपुंज टक्याली दरें बदलती रहती हैं, क्योंकि वे तो मिट्टी के असली सोने का पारिमाणिक संबंध-मात्र हैं । परंतु ऐसी परिस्थिति-वाले देशों में टक्याली दर, जिनमें एक का स्टैंडर्ड-सिद्धा तो सोने का और दूसरे का चांदी का हो, हमेशा बदलती रहती हैं । कारण, चांदी की सोने में कीमत बदलती रहती है । यही दशा भारत में सन् १८६३ ई० के पहले थी । हमारा स्टैंडर्ड-सिद्धा रपया चांदी का था, और इंगलैंड तथा अन्य देशों का सोने का । अतएव जैसे-जैसे चांदी की सोने में कीमत बढ़ती, वैसे-वैसे भारत की टक्याली दर भी बढ़ती गई । परंतु अब तो भारत में कोई स्टैंडर्ड-सिद्धा है ही नहीं । रपय की बाह्य कीमत, उसमें जो चांदी है, उसकी कीमत से अधिक है । इसलिये अब भारत और अन्य देशों में बीच में कोई टक्याली दर नहीं हो सकती । भारत-सरकार ने जानून बनाकर पहले रपय की दर एक शिलिंग चार पेंस नियत की थी, और फिर सन् १९२० ई० में एक रपया दो शिलिंग के बराबर मान रक्खा है ।

अंतरराष्ट्रीय मिश्रण—इस समय विष-विष देशों में और बहुत-बहुत एक ही देश के विविध भागों में अनेक प्रकार के सिक्के प्रचलित हैं । हरएक को अपने अपने सिक्के का अभिमान है । इसने बड़ी असुविधा होती है । यदि भविष्य-भर में एक सिक्के का प्रचलन हो, तो निम्न-लिखित कई लाभ हों—

पारिक संबंध है। सबसे अधिक व्यापार नेपाल से होता है। उसके बाद क्रमशः शान-राज्य और अफ़ग़ानिस्तान का नंबर है। नेपाल से विशेष कर चावल, तेलहन, घी, घा, गऊ, बैल, भेड़, बकरे आते हैं, और बदले में कपड़ा, चीनी, नमक, धातु के बर्तन इत्यादि जाया करते हैं। शान-राज्यों से घोड़े, टट्टू और ख़च्चर, श्याम और फरीनी से लकड़ी, तिब्बन से परम और उन तथा अफ़ग़ानिस्तान से ऊन और फल इत्यादि सामान आते हैं, और बदले में सूती कपड़ा, चा, चीनी, नमक, मसाला, धातु के बर्तन आदि जाया करते हैं।

काश्मीर और शान-राज्यों के साथ जो भारतवर्ष का व्यापार होता है, उसे वास्तव में विदेशी व्यापार नहीं कह सकते। परंतु सरकारी रिपोर्ट में इसका हिसाब विदेशी व्यापार में ही दिया जाता है।

भारतीय जहाज़ों का हास •—अपनी वस्तुओं को विदेशों में ले जाने और विदेशी माल लाने के लिये उन्नत देश अपने ही जहाज़ों का उपयोग करते हैं। प्रार्थन काल में समृद्धिशाली व्यापारी-वर्ग के उत्साह तथा शक्ति, केवटों की कुशलता तथा साहस और पोत-निर्माण एवं सामुद्रिक व्यापार की ग़ज़ब की उन्नति के कारण ही भारत सैकड़ों वर्षों तक पूर्व के समुद्रों पर प्रभुत्व बनाए रहा।

डा० राधाकुमुद मुन्शी का मत है कि सन् १८४० ई० से यहाँ जहाज़ बनाने के उद्योग का नाश होने लगा। उसके बाद एक भी बड़ा जहाज़ नहीं बनाया गया। भारत का राज्याधिकार कंपनी के हाथ से निकलकर ईंगलैंड के बादशाह के हाथ में चले जाने के थोड़े ही समय बाद, अर्थात् सन् १८६३ में, यह काम बिल्कुल बंद कर दिया गया। इसका कारण यह था कि भारतीय जहाज़ों पर भारत-वासियों को ही नौकर रखना पड़ता था। इस बात को 'देश-भङ्ग' अंगरेज़ सहन न कर सके। उन्होंने अपना रोज़गार चौपट होते

• भारत-दर्शन" के आधार पर।

देश	१९१३-१४ (महायुद्धके पूर्व)	१९१९-२०	१९२२-२३ *
	जहाजों की संख्या	जहाजों की संख्या	जहाजों की संख्या का कुल संख्यासे अनुपात की सिकड़ा
ब्रिटिश	४,९६१	४,३४०	७४.२
ब्रिटिश-इंडिया	२०३	४४२	३.३
जापान	१६१	४०६	६.८
अमेरिका	—	८६	१.७
हालैंड	१३१	७२	३.३
इटली	७३	८२	३.१
नार्वे	८०	१०४	१.१
स्वीडन	१३	३०	.३
ग्रोस	६०	३८	.२
बोल	—	२०	.०४
यूनान	२६	१२	.१
रूस	४४	१८	—
जर्मनी	२२२	—	२.६
स्पेन	—	१२	.२
आस्ट्रिया-हंगरी	२८२	—	—
सम्य राष्ट्र	४	२२	.२६
देती नौकर	—	—	.८
योग	६,६२०	२,०६६	१००

* १९ वर्षों के कुल जहाजों की संख्या ७,४०६ थी ।

मुद्र-द्वार-व्यापार होने की दशा में देश के व्यापारी विदेशी व्यापारियों से प्रतियोगिता करते हैं । इससे उनमें अपना माल सस्सा तैयार करने की शक्ति और योग्यता आ जाता है । संरक्षण-नीति में यह बात नहीं होने पाती । पुनः प्रकृति ने प्रत्येक देश को सभी आवश्यक सामग्री नहीं प्रदान की है, इसलिये यदि हम अन्य देशों से आनेवाले माल पर अधिक कर लगावेंगे, तो दूसरे देशवाले अपने वहाँ आनेवाले हमारे माल पर वैसा ही कर लगाकर हमसे बदला भी लेंगे । इसमें हमारा-उनकी आपस में तनातनी रहेगी ।

इन नीतियों का व्यवहार—ये बातें तो केवल सिद्धांत की हैं । वास्तव में प्रत्येक देश अपनी व्यापार-नीति, अपने परिस्थिति के अनुसार स्थिर करता है, और उसे आवश्यकतानुसार बदलता भी है । योरोप के जो बहुत-से राष्ट्र अब मुद्र-द्वार-व्यापार की प्रशंसा कर रहे हैं, वे ही कुछ समय पहले तक अपने व्यापार की संरक्षणनीति से रक्षा कर रहे थे । महायुद्ध के समय में एक बार फिर उन्होंने संरक्षण-नीति से ही लाभ उठाया है ।

अमेरिका के समृद्धिशाही होने की बात कान नहीं जानना । योरोप के साथ सब बड़े राष्ट्र उसके कर्जदार हैं । फिर भी वह विदेशी माल को अपने वहाँ से रोक-टोक नहीं आने देता । सितंबर, १९२२ ई० में उसने टैरिफ-बिल पासकर दिया है, जिसमें उसने आयात पर १० से लेकर ४० सेंकड़े तक कर घटाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है । इसके साथ वह अपने वहाँ स्थानिक और रजिस्ट्री-मुद्रा व्यापारिक कंपनियों को, विदेशों में माल ले जाने के लिये, बहुत ही सस्ते दाम पर उहाड़ देता है । फिर जिस अहाज से जिनका माल जाना है, उसे उसी अनुमान में बहुत हानि भी मिलता है । ये महायुद्ध देने के लिये वहाँ की जन-मन में, सन पूर्व वर्ष २०

ज़र, रात २५ सितंबर, सन् १९२२ ई० को कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई । पाँच योरोपियन तथा दो हिंदोस्तानी मेंबरों की बहुमत रिपोर्ट चलन है, और शेष पाँच भारतीय सदस्यों की (जिनमें अध्यक्ष महोदय भी हैं) अल्पमत रिपोर्ट पृथक् है ।

संरक्षण की आवश्यकता—समस्त—अल्पमत और बहुमत—कमीशन का मत है कि भारतवर्ष की औद्योगिक उन्नति, उसके आकार, जन-संख्या तथा प्राकृतिक साधनों के अनुसार संतोषजनक नहीं हुई । भारत ही के उद्योग-धंधों की उन्नति भारत को विशेष लाभ हो सक्ता है । औद्योगिक उन्नति शीघ्र हो, इसके लिये समय अनुवृक्ष है ; पर संरक्षण-नीति का आश्रय लिए बिना शीघ्र उन्नति न हो सकेगी ।

व्यवहार-विधि में मत-भेद—परंतु संरक्षण-नीति का व्यवहार किस प्रकार किया जाय, इस विषय में मत-भेद है । बहुमतवालों की सिफारिश है कि भारत की औद्योगिक उन्नति के लिये, उनकी रिपोर्ट में बताए गए नियम के अनुसार, उद्योग-धंधों पर चुन-चुनकर अथवा सोच-समझकर रक्षण-कर बैठाया जाय । साथ ही इस बात का भी ध्यान रक्खा जाय कि इसमें जनता को अधिक कर का बोझ न उठाना पड़े ।

किंतु अल्पमतवाले सज्जनों ने बहुमत की यह बात नार्मजर की है । उनका कथन है कि संरक्षण-मार्ग की ये बाधाएँ व्यर्थ हैं । औद्योगिक उन्नति के लिये धारम में आयात-वस्तुओं पर इतना अधिक महसूल लगाया जाय कि विदेशी माल सस्ता न बिक सके । अल्प-मत शराब, तंबाकू तथा अन्यान्य विजास की वस्तुओं को छोड़कर देश में बननेवाले अन्य किसी माल पर कर बैठाने के पक्ष में नहीं है ।

कहना नहीं होगा कि अल्पमत ही भारतीय नेताओं का मत है,

द्वैत, रात २५ सितंबर, सन् १९२२ ई० की कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई । पाँच योरपियन तथा दो हिंदोस्तानी मंत्रों की बहुमत रिपोर्ट अलग है, चार शेष पाँच भारतीय सदस्यों की (जिनमें अध्यक्ष महोदय भी हैं) अल्पमत रिपोर्ट पृथक् है ।

संरक्षण की आवश्यकता—ममल—अल्पमत और बहुमत—कमीशन का मत है कि भारतवर्ष की औद्योगिक उन्नति, उसके आकार, जन-संख्या तथा प्राकृतिक साधनों के अनुसार संतोषजनक नहीं हुई । भारत ही के उद्योग-धंधों की उन्नति से भारत को विशेष लाभ हो सकता है । औद्योगिक उन्नति शीघ्र हो, इसके लिये समय अनुपलब्ध है ; पर संरक्षण-नीति का आश्रय लिए बिना शीघ्र उन्नति न हो सकेगी ।

व्यवहार-विधि में मत-भेद—परंतु संरक्षण-नीति का व्यवहार किस प्रकार किया जाय, इस विषय में मत-भेद है । बहुमतवालों की सिफारिश है कि भारत की औद्योगिक उन्नति के लिये, उनकी रिपोर्ट में बताए गए नियम के अनुसार, उद्योग-धंधों पर चुन-चुनकर अथवा सोच-समझकर रक्षण-कर बैठाया जाय । साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि इसमें जनता को अधिक कर का बोझ न उठाना पड़े ।

किंतु अल्पमतवाले सज्जनों ने बहुमत की यह बात नामंजूर की है । उनका कथन है कि संरक्षण-मार्ग की ये बाधाएँ व्यर्थ हैं । औद्योगिक उन्नति के लिये आरंभ में आयात-वस्तुओं पर इतना अधिक महसूल लगाया जाय कि विदेशी माल सस्ता न बिक सके । अल्प-मत शराब, तंबाकू तथा अम्यान्स विलास की वस्तुओं को छोड़कर देश में बननेवाले अन्य किसी माल पर कर बैठाने के पक्ष में नहीं है ।

कहना नहीं होगा कि अल्पमत ही भारतीय नेताओं का मत है,

विलकुल ही कर लड़ना चाहिए। ऐसे माल पर— जो आधा विदेश में बना हो, परंतु तैयार भारत के कारखाने में होता हो—कम से-कम महसूल लिया जाय। जिन वस्तुओं के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन पर कितना कर लगाना चाहिए, इसका निर्णय भारत-सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करे।

अल्पमत ने टैरिफ-बोर्ड की आवश्यकता स्वीकार तो की है, पर उसकी राय में बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो हाई-कोर्ट की जजों के पद पर कार्य कर चुका हो, और बोर्ड के अन्य दोनों सभासदों का चुनाव व्यवस्थापक सभा के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत की दो प्रधान व्यापारिक संस्थाओं की ओर से चुने गए दो प्रतिनिधि भी बोर्ड में रहें, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड बुला लिया करे।

सरकार का निश्चय—प्रचुरी, सन् १९२३ ई० में भारतीय व्यवस्थापक सभा में उक्त आर्थिक कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हुआ। श्रीयुक्त जमनादास-द्वारकादासजी ने यह प्रस्ताव किया कि “यह सभा सपरिपद गवर्नर जनरल से अनुरोध करती है कि भारतके हितों की रक्षाके लिये संरक्षण नीति उपयोगी है, भारत सरकार व्यवस्थापक सभा की अनुमति से उसका उपयोग करे।” प्रस्ताव को पेश करते हुए आपने बतलाया कि अब तक हम संबंध में सरकारी नीति बहुत अनुचित रही है, और अब उसमें परिवर्तन होना चाहिए।

आपके कथन के अनंतर ही सरकार की ओर से मि० इनीज़ ने यह संशोधन पेश किया—

“यह सभा सपरिपद गवर्नर जनरल से अनुरोध करती है कि [क] यह यह सिद्धान्त स्वीकृत करनी है कि भारत-सरकार की भावी नीति भारतीय उद्योग-धंधों की उन्नति की ओर अभिमुख हो जाय, [ख] संरक्षण के सिद्धान्त का उपयोग करने में भारत की आर्थिक आवश्यक-

खिलकुल ही कर न लगाना चाहिए। ऐसे माल पर— जो आधा विदेश में बना हो, परंतु तैयार भारत के कमराने में होता हो—कम से-कम महसूल लिया जाय। जिन वस्तुओं की संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन पर कितना कर लगाना चाहिए, इसका निर्णय भारत-सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करे।

अल्पमत ने टैरिफ-बोर्ड की आवश्यकता स्वीकार तो की है, पर उसकी राय में बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो हाई-कोर्ट की जज के पद पर कार्य कर चुका हो, और बोर्ड के अन्य दोनों सभासदों का चुनाव व्यवस्थापक सभा के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा होना चाहिए। इसके अनतिरिक्त भारत की दो प्रधान व्यापारिक संस्थाओं की ओर से चुने गए दो प्रतिनिधि भी बोर्ड में रहे, जिनके आवश्यकता परने पर बोर्ड बुला लिया करे।

सरकार का निश्चय—प्रथमी, सन् १९२३ ई० में भारतीय व्यवस्थापक सभा ने उक्त आर्थिक कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हुआ। धीपुन जमनादास-द्वारादासजी ने यह प्रस्ताव किया कि "यह सभा सरतिपद गवर्नर जनरल से अनुरोध करती है कि भारतके हिनों की रक्षाके लिये संरक्षण नीति उपयोगी है, भारत सरकार व्यवस्थापक सभा की अनुमति से उसका उपयोग करे।" प्रस्ताव को पेश करते हुए आपने बयलाया कि अब तक हम संदेह से सरकारी नीति बहुत अनुचित रही है, और अब उसमें परिवर्तन होना चाहिए।

आपके कथन के अनंतर ही सरकार की ओर से मि० इलीज ने यह संशोधन पेश किया—

"यह सभा सरतिपद गवर्नर जनरल से अनुरोध करती है कि [क] यह वह सिद्धांत स्वीकृत करती है कि भारत-सरकार की भारी नीति भारतीय उद्योग-धंधों की उत्थिति की ओर अग्रसर की जाए, [ल] संरक्षण के सिद्धांत का उपयोग करने से भारत की आर्थिक उत्थिति—

बिलकुल ही बर म लगाना चाहिए। ऐसे माल पर— जो आया विदेश में बना हो, परंतु मयार भारत के कारखाने में होता हो—कम से-कम महसूल लिया जाय। जिन वस्तुओं के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन पर कितना कर लगाना चाहिए, इसका निर्णय भारत-सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करे।

अन्तरिम ने टैरिफ-बोर्ड की आवश्यकता स्वीकार तो की है, पर उसकी राय में बोर्ड का अध्यक्ष म्मा प्यत्रि होना चाहिए, जो हाई-कोर्ट की जर्जी के पद पर कार्य कर चुका हो, और बोर्ड के अन्य दोनों समानों का चुनाव व्यवस्थापक सभा के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत की दो प्रधान व्यापारिक संस्थाओं की ओर से चुने गए दो प्रतिनिधि भी बोर्ड में रहे, जिन्हें आवश्यकता पड़े पर बॉर्ड बुला लिया करे।

सरकार का निश्चय—ब्रवरी, सन् १९२३ ई० में भारतीय व्यवस्थापक सभा में उन्न आधिक कर्माशन की रिपोर्ट पर विचार हुआ। ध्यापुत जमनादाम-द्वारकादामजी ने यह प्रस्ताव किया कि "यह सभा सरतिपद् गवर्नर जनरल से अनुरोध करती है कि भारतके हितों की रक्षाके लिये संरक्षण नीति उपयोगा है, भारत सरकार व्यवस्थापक सभा की अनुमति से उसका उपयोग करे।" प्रस्ताव को पेश करते [१] आपने बतलाया कि अब तक हम सबध में सरकारी नीति बहुत अनुचित रही है, और अब उसमें परिवर्तन होना चाहिए।

आपके कथन के अनंतर ही सरकार की ओर से मि० पद संशोधन पेश किया—

"यह सभा सरतिपद् गवर्नर जनरल से अनुरोध पर पद मिर्दान स्वीकृत करनी है कि भारतीय उपयोग-धर्मों की संरक्षण के मिर्दान का"

कि यह प्रस्ताव भारत-मंत्री की राय से किया गया है, और भारत-मंत्री को इसमें ईंगलैंड के व्यापारियों को बचाने की काफी गुंजाइश मिल गई है।

आखिर इस प्रस्ताव से लाभ ही क्या हुआ ? आर्थिक कमीशन का आदंबर रखने और उसमें इतना धन तथा परिश्रम नष्ट करने की क्या आवश्यकता थी ? कहा जा सकता है कि सरकार ने संरक्षण-मित्रांश को मान लिया। परंतु इस प्रकार मुरझात में, दबी जवान में कोई बात स्वीकार करने से, जब तक कि वह यथेष्ट रूप से कार्य में परिणत न हो, क्या फायदा ?

भारत का हित संरक्षण में है—भारतीय चरम-शास्त्र-वेत्ताओं—
 एच० श्री० गोमले, जस्टिस रानाडे और श्री० रामेशचंद्र दत्त—और
 निम्नलिखित जेनकों ने भी यह स्वीकार किया है कि भारत के
 हित की दृष्टि से यहाँ संरक्षण-नीति का ही व्यवहार होना चाहिए।
 इससे निम्न-लिखित कई लाभ होंगे—

(१) करीब ७५ वर्ष पहले ईंगलैंड ही को भारतवर्ष से कपड़ा
 जाता था। पर ईंगलैंड ने संरक्षण-कर लगाकर इस व्यापार को चौपट
 कर दिया। संरक्षण-नीति का अख हाथ में आते ही मैचिस्टर की
 'इंफिंग' अर्थात् अपना माल घाटे पर भी निकाल देने की स्वार्थमय
 नीति का प्रतिकार करना भारत के लिये कुछ भी कठिन न होगा,
 और वह अपना व्यापार चमका सकेगा।

(२) चमड़े के व्यापार में भारत से कच्चा चमड़ा बाहर जाता
 और आस्ट्रेलिया से कमाया हुआ चमड़ा यहाँ आता है। संरक्षण-
 नीति ॥ इस व्यापार में बढ़ी उद्यति होगी।

(३) भारत को जीवन-निर्वाह की सामग्री किसी ॥ नहीं लेनी
 पड़ती। अतएव यदि अन्य देशवाले यहाँ आनेवाली आराम की वस्तुओं
 पर महसूल लगा दें, तो भी भारत को कोई हानि नहीं। और, वे यहाँ
 से जानेवाले कच्चे माल पर तो टैक्स लगा ही नहीं ॥ अतः, क्योंकि उन्हें

बाहर जाने से भयंकर दुमिहों की विकराखता और भी बढ़ जाती है। इनसे बचने के लिये आवश्यक यह है कि निर्यात पर थोपेट कर लगाया जाय। अन्य पदार्थों में अन्न, रई और तेलहन पर तो कर लगाना नितांत आवश्यक है। अन्न के निर्यात पर कर लगाने से यहाँ मंहगी कम होगी। रई के निर्यात पर कर लगाने से हमारे स्वदेशी वस्त्र के व्यवसाय की उन्नति होगी, चर्खा चलानेवालों को थोपेट सामग्री तथा कार्य मिलेगा, घसंख्य अमाधों, विधवाओं और दरिद्रों की आजीविका चलेगी, देश के जुलाहों और अन्य कारीगरों को स्वतंत्रता-पूर्वक निर्वाह करने का साधन प्राप्त होगा, तथा विदेशी वस्त्रों में व्यव होनेवाला धन स्वदेश ही में रहकर यहाँ के निवासियों की सुख-समृद्धि में सहायक होगा। इसी प्रकार तेलहन को विदेश भेज कर यहाँ से तेल मँगाने में हमें इस समय जो हानि हो रही है, वह उसके निर्यात पर थोपेट कर लगाने से दूर हो सकती है।

व्यापारियों का वर्तमान— हमने बतलाया है कि यहाँ विदेशों से आनेवाले सवार माल पर आयात-कर एवं यहाँ से बाहर जाने वाले कच्चे माल पर निर्यात-कर लगाना बहुत जरूरी है। परंतु वर्तमान परिस्थिति में (यद्यपि हमें कहने की तो आधिक स्वराज्य प्राप्त है) इन कर का थोपेट मात्रा में लगाया जाना संभव नहीं दिखता। ईंगलैंड के मंत्रियों को और यहाँ की सरकार को भी ईंगलैंड (यद्यपि साम्राज्य) के हितों की इतनी अधिक चिंता है कि भारत के कल्याण का बहुतो बलिदान कर दिया जाता है। इसका समुचित प्रतिफल स्वराज्य प्राप्त होने पर ही हो सकेगा। उसके लिये जी-अन उद्योग करना प्रत्येक नागरिक का प्रधान कर्तव्य है—यह है परंतु प्रश्न तो यह है कि उस समय तक क्या किया जाय ?

देश के अन्तार पर व्यापारियों का हो बहुत कुछ अधिकार रहता है। दुःख की बात है कि इस समय शासकों के अतिरिक्त हम

साम्राज्य-संबंधी व्यापार की कीमत और स्वरूप—इस नीति के प्रभाव को समझने के लिये पहले भारतवर्ष के आयात और निर्यात की कीमत और स्वरूप जान लेना चाहिए।

कीमत जानने के लिये यहाँ तुलनात्मक अंक दिए जाते हैं—

देश	१९१३-१४ में भारत का (करोड़ रुपये में)		१९२१-२२ में भारत का (करोड़ रुपये में)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
ब्रिटिश-द्वीप ईंग्लैंड के अधीन प्रान्त देश	५८	११७	४६	१५१
ब्रिटिश-साम्राज्य का योग	६४	१२८	१०१	१७७
यूरोप	८५	३०	४७	२३
अमेरिका के संयुक्त- राज्य	२२	५	२६	२२
जापान	२३	५	३६	१४
शेष अन्य देश	२५	१५	३२	३०
साम्राज्य के बाहर के कुछ देश	१५५	५५	१४४	८६
समस्त योग	२४६	१८३	२४५	२६६

आने में भारत का कुछ विरोध मुकमान नहीं होगा। परंतु यहाँ के चावल और चा के बिना आस्ट्रेलिया के निवासियों के भूखे रहने की संभावना है।

साम्राज्यांतर्गत रियायत से इंग्लैंड का अपरिमित लाभ—सन् १९२१-२२ ई० में भारतवर्ष के आयात का प्री-संकट ५६.७ मूल्य का माल इंग्लैंड से आया। असहयोग-आंदोलन आदि कारणों के न होने की दशा में, आसत से यहाँ ६१ प्री-संकट मूल्य का माल इंग्लैंड से आता है। इसमें से कपड़े को छोड़कर अन्य चीजें यहाँ की प्रधान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। और, कपड़ा यहाँ तैयार हो सकता है। इसलिये उन पर अधिक टैक्स लगाकर भारतवर्ष बिना कष्ट भोगे इंग्लैंड की क्षति पहुँचा सकता है, तथा उसके प्रतिपक्षी देशों का व्यापार और स्वयं अपने उद्योग-धंधे बढ़ा सकता है।

यदि भारतवर्ष साम्राज्यांतर्गत रियायत की नीति मान ले, तो—

(क) कर कम लगने से यहाँ इंग्लैंड का माल अन्य देशों के माल से सस्ता पड़ेगा। अतः दूसरे देशों का माल यहाँ न बिक सकेगा। और, तब यहाँ का बाजार पूर्ण रूप से इंग्लैंड के हाथ चला जायगा।

(ख) इंग्लैंड की यहाँ का कच्चा माल अन्य देशों की अपेक्षा अधिक मात्रा में एवं सस्ते दाम पर मिलेगा, और उसके व्यापारिक (प्रकारांतर से राजनीतिक) बल की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जायगी।

भारतवर्ष को कोई लाभ नहीं—भारतवर्ष की निर्यात की चीजों पर इंग्लैंड में कर की रियायत तभी हो सकती है, जब यहाँ वे चीजें किसी अन्य देश से आती हों, और भारतवर्ष की चीजों से मुकाबला करना पड़ता हो। इंग्लैंड के साथ चावल और कच्चे थमड़े के व्यापार में भारतवर्ष को किसी से मुकाबला नहीं करना पड़ता।

‘मदा’ मँदगे बाज़ार में बेचना और सस्ते भाव में खरीदना’ । इस समय भारतवर्ष के कच्चे माल के लिये शारे संसार का बाज़ार खुला हुआ है, इसलिये खरीदारों में बढ़ावदी होने के कारण यहाँ के माल के अच्छे दाम लगने हैं । पर ‘रियायत’ की नीति से इन चीज़ों के लिये एक ही बाज़ार रह जायगा, और कीमत निश्चित करने में खरीदार का ही खोजबाला रहेगा ।

(ख) इसी प्रकार यहाँ जो माल बाहर में तैयार होकर आता है, उसमें भी बाहर के देशों में बढ़ावदी है, जिसके कारण हमें चीज़ें सस्ती मिलती हैं । पर ‘रियायत’ की नीति से इंगलैंड को बढ़ावदी का डर नहीं रहेगा, और हमें उसकी चीज़ें अधिक दाम पर खरीदनी पड़ेंगी ।

(ग) किन्तु सबसे अधिक भय यह है कि जिन देशों के माल पर, इंगलैंड के ख़ास के लिये, हम अधिक कर लगायेंगे, वे भी, हमसे बढ़ावा लेने के लिये, भारत के निर्यात-व्यापार पर अधिक कर लगा देंगे, जिससे या तो हम यह कर देकर धाट्य सहेंगे, या इंगलैंड के व्यापारियों की मनमानी कीमत पर उन्हीं के हाथ अपना माल बेचा करेंगे । इस प्रकार प्रत्येक दशा में हमारी हानि और इंगलैंड का लाभ होगा ।

(घ) अन्य देशों का जो माल यहाँ आवेगा, उस पर भी इंगलैंड की दुकाली लगेंगी । संभव है, जो चीज़ें इंगलैंड में नहीं बनती, उन्हें इंगलैंड के लोभी व्यापारी दूसरे देश में मँगाकर भारत-वर्ष में अपने नाम से बेचने लगें । इससे निर्दल भारतवासियों को अपनी ज़रूरत की सब चीज़ों के लिये अधिक दाम देने पड़ेंगे ।

(च) इस समय लगभग ६१ क़ी-सदी माल यहाँ इंगलैंड से ही आता है । कर कम हो जाने पर यह और भी अधिक आने लगेगा । और, तब आयात-कर की कमी से भारत-सरकार की आमदनी में

या न मानना उसकी इच्छा पर ही निर्भर रहना चाहिए। परन्तु स्वराज्य के बिना अपनी "इच्छा" क्या ?

आन्तरिक ने प्रिटिग-नीति अथवा प्रिटिग-उपनिवेशों के संबंध में साम्राज्यांतर्गत संरक्षण-नीति प्रदत्त करने का विशेष किया है। उसकी राय है कि भारत को जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता, और जब तक पूर्णतः निर्वाधित व्यवस्थापक-सभा भारत की अर्थ-नीति का संचालन नहीं करती, तब तक भारत साम्राज्यांतर्गत संरक्षण-नीति नहीं प्रदत्त कर सकता। इस नीति के संबंध का पूर्ण अधिकार—यदि आज हो इसके अवलंबन करने की आवश्यकता हो तो—व्यवस्थापक-सभा के गैर-सरकारी सदस्यों को रहना चाहिए। साम्राज्य के अन्योन्य उपनिवेशों के लिये इस नीति के प्रदत्त करने का निर्णय पारस्परिक हितों की दृष्टि से होना चाहिए। परन्तु इसके लिये पहली शर्त यह होनी चाहिए कि उपनिवेशों में भारतीयों को समानाधिकार दिए जायें, और एशिया-निवासियों के विरुद्ध वे कानून रद्द कर दिए जायें, जिनका संबंध भारतवासियों से हो।

षष्ठ खंड



उस पर उत्पत्ति-व्यय ३) फ्री मन पड़ता है । अस्तु, जब जन-संख्या की वृद्धि ■ कारण अन्न की माँग बढ़े, और इस ज़मीन की जोतना पड़े, तो बाज़ार-दर ३) मन होगी । इससे अच्छी ज़मीनवाले को प्रति मन १) का अर्थात् ४० मन में ४०) का लाभ होगा ।

कल्पना कीजिए कि जन-संख्या के और भी बढ़ जाने से अब और अधिक दूरवाली कम उपजाऊ ज़मीन के जोतने की आवश्यकता पड़ी । उसकी उपज फ्री एकड़ २० मन और उत्पत्ति-व्यय ४) फ्री मन है । अब बाज़ार-दर फ्री ४) मन होगी । इसलिये पहले दर्जे की भूमिवाले को २) प्रति मन अर्थात् ४० मन पर ८०) लाभ होगा, और दूसरे दर्जे की भूमिवाले को १) प्रति मन अर्थात् ३० मन उपज पर ३०) लाभ होगा ।

रिकाड़ों के सिद्धांत के अनुसार यह अधिक लाभ ही 'आर्थिक' खगान होगा। यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि यह खगान भूमि के उपजाऊपन के कारण नहीं खग रहा है, बल्कि कम उपजाऊ भूमि के कारण । इस सिद्धांत में हमें यह मानना पड़ता है कि एक भूमि ऐसी भी होती है, जिसमें खगाए हुए श्रम और पूँजी के बदले उतने से ज्यादा और कुछ उत्पन्न नहीं होता, और इसी भूमि के आधार पर और भूमि के खगान का निश्चय होता है । ऐसी भूमि को कृषि की सबसे निकृष्ट भूमि कहते हैं । इस भूमि में पदार्थों का जो उत्पादन-व्यय होगा, वह उन पदार्थों का बाज़ार-भाव होगा (यदि बाज़ार ■ दाम कम लगे, तो उस भूमि पर कोई खेती ही न करे) । इससे अच्छी भूमि की उपज का उत्पादन-व्यय कम होता है, और दाम बाज़ार-भाव से हो मिलते हैं । इसलिये उसमें खेत करनेवालों को लाभ रहता है, अर्थात् उन्हें खगान मिलता है । इस प्रकार खगान बाज़ार-भाव का कारण नहीं, बल्कि उसका परिणाम है ।

कर ऐसी अच्छी तरह रोनी नहीं करते, जैसे मौसमी कारतकार । इससे देश की उपज नहीं बढ़ती, और किसानों की दशा दिन-पर-दिन खराब होती जाती है ।

ज़मींदारों से बेदखली का अधिकार वापस लेकर इस कुप्रथा का अंत किया जाना चाहिए । कारतकारी-क़ानून में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय कि ग़ैर-मौसमी कारतकारों को, जो तीन साल रोनी कर चुके हों, मौसमी इक़्त प्राप्त हो जाय । और, जिन्हें रोनी करते कम समय हुआ हो, उन्हें उस अवधि के पूरी होने पर मौसमी इक़्त प्राप्त हो जाय ।

बेदखली का नियम हटाने के लिये किसानों को भी संगठित रूप से आंदोलन करना चाहिए । आजकल जगह-जगह किसान-सभाएँ स्थापित हो रही हैं । वे किसानों के विविध कष्टों को दूर करने का बीड़ा उठा सकती हैं । देश-हितियों को इनको वृद्धि और विस्तार में योग देना चाहिए ।

अस्थायी बंदोबस्त—अस्थायी बंदोबस्तवाले प्रांतों में सरकारी मालगुजारी एक बार केवल तीस, बीस या इससे कम सालों के लिये निश्चित की जाती है । इस अवधि के उपरांत हर समय नया बंदोबस्त होता है, जिसमें बहुधा मालगुजारी का भार बढ़ता ही रहता है । अस्थायी बंदोबस्त दो प्रकार का है—

(क) ज़मींदारी, तालुकदारी या ग्राम्य—इसमें ज़मींदार या तालुकदार अपने हिस्से की, जबका गाँववाले मिलकर कुछ गाँव की मालगुजारी सरकार को चुकाने के लिये उत्तरदायी होते हैं ।

(ख) रियासती—इसमें सरकार सीधे कारतकारों से संबंध रखती है ।

बंदोबस्त का क्षेत्रफल—बंदोबस्त की मिश्र-मिश्र प्रणालियों के क्षेत्र का मोटा हिस्सा नीचे दिया जाता है । इसमें बंजर, पानी

कर ऐसी अच्छी तरह लेती नहीं करते, जैसे मौसमी बाग़ान। हमारे देश की उपज नहीं बढ़ती, और किसानों की दशा दिन-प्र-दिन खराब होती जाती है।

ज़मींदारों से बेदख़ली का अधिकार वापस लेकर हम कुम्हटा का संत किया जाना चाहिए। कारतकारी-क़ानून में ऐसा परिष्कार कर दिया जाय कि ग़ैर-मौसमी कारतकारों को, जो नान माल लेनी कर चुके हों, मौसमी हक़ प्राप्त हो जाय। और, उन्हें लेनी करते कम समय हुआ हो, उन्हें उम अवधि के पूरी होने पर मौसमी हक़ प्राप्त हो जायें।

बेदख़ली का नियम हटाने के लिये किसानों को भी संगठित कर से आंदोलन करना चाहिए। आजकल जगह-जगह किसान-समाज स्थापित हो रही हैं। वे किसानों के विविध कष्टों को दूर करने का बीड़ा उठा सकती हैं। देश-हिन्दियों को इनकी वृद्धि और विस्तार में योग देना चाहिए।

अस्थायी बंदोबस्त—अस्थायी बंदोबस्तवाले प्रांतों में सरकारों मालगुजारी एक बार केवल तीस, बीस या इससे कम सालों के लिये निश्चित की जाती है। इस अवधि के उपरान्त हर समय नया बंदोबस्त होता है, जिसमें बहुधा मालगुजारी का भार बढ़ता ही रहता है। अस्थायी बंदोबस्त दो प्रकार का है—

(क) ज़मींदारी, तालुकदारी या ग्राम्य—इसमें ज़मींदार या तालुकदार अपने हिस्से की, चायवा गाँववाले मिलकर कुछ गाँव की मालगुजारी सरकार को चुकाने के लिये उत्तरदायी होते हैं।

(ख) रियतदारी—इसमें सरकार सीधे कारतकारों से रक़ब रखती है।

बंदोबस्त का क्षेत्रफल—बंदोबस्त की मित्र-मित्र प्रकाशिकों के क्षेत्र का मोटा हिस्सा भीचे दिया जाता है। इसमें

दस्तूर, आवादी और स्पर्दा का प्रभाव—पहले यहाँ जब तक कोई कृषक दस्तूर के माफ़िक लगान देता रहता था, तब तक तो वह अपनी इच्छा के विरुद्ध बेदखल नहीं कराया जा सकता था। पीछे समय-समय पर युद्ध, महँगी और बीमारियों के कारण भारत-वर्ष के उपजाऊ भागों की भी आवादी कम हो गई, और ज़मींदारों को, दूर-दूर के कृषकों को अपनी भूमि की ओर आकर्षित करने लिये, आपस में स्पर्दा और कृषकों के साथ रियायत करनी पड़ी। इस प्रकार लगान-संबंधी दस्तूर टूटने लगा।

किंतु आजकल एक दूसरे कारण से भी दस्तूर टूट रहा है। जनता की वृद्धि होने और उपज के बाज़ार का क्षेत्र बढ़ने से भूमि की माँग बढ़ गई है। और, ज़मीन ऐसी चीज़ है, जिसकी पूर्ति नहीं बढ़ सकती। सन् १८६० ई० से लगान प्रायः ठेके से निरिचत होने लगा है। हाँ, दस्तूर का कुछ बिहाज़ ज़रूर रहता है। ब्रिटिश-शासन के प्रारंभिक समय तक यहाँ दस्तूर का प्रभाव बहुत पड़ता था। जब एक ज़िले की दूसरे ज़िले से तो विशेष स्पर्दा नहीं होती। परंतु एक ही गाँव में यह बहुधा सीम होती है।

कंपनी की अनीति—पहले भारतवर्ष में ज़मीन पर कृषक का अधिकार समझा जाता था, सरकार या ज़मींदार का नहीं। परंतु व्यापार-रत स्वार्थी ईस्ट इंडिया-कंपनी ने इस देश की अपनी ज़मींदारी समझा, और कठोरता तथा निर्दयता-पूर्वक, ज़मादा-से-ज़मादा जितनी माजगुज़ारी वह वसूल कर सकी, उसूल की। इस अनीति का फल यह हुआ कि ज़मीन परती पड़ी रहने लगी, कारतकार भूखों मरने लगे। तब अधिकारियों को यह ख़याल आया कि यह स्थिति अच्छी नहीं। जब ज़मीन जोती हो न जायगी, तो माजगुज़ारी कहाँ से ली जायगी ?

बंगाल में स्थायी बंदोबस्त—अंततः लॉर्ड कार्नवालिस ने

में अपना हिस्सा २० फ्री सदी ठहराना पड़ा। सन् १८६४ ई० में यही नियम भारतवर्ष के दक्षिणी प्रांतों में कर दिया गया। लेकिन हमसे वास्तव में लाभ जमींदारों को ही हुआ। अब किसानों के बारे में मुनि—

काश्तकारी ज़मानून—क्रमशः जन-संख्या-वृद्धि और औद्योगिक हास के कारण अधिकाधिक भूमि में खेती होने लगी, और भूमि की माँग बढ़ती गई। परंतु भूमि की मात्रा परिमित ही थी। अतएव जमींदारों ने अपनी भूमि का लगान बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे किसान बहुत दुःखी होने लगे। इस पर सन् १८५६ ई० में सरकार ने इस विषय की और पहलेपहल ध्यान दिया। सन् १८८५ ई० में बंगाल-टिनेसी (Tenancy) या काश्तकारी-ऐक्ट पास हुआ। इससे पहले के नियमों की त्रुटियाँ दूर की गईं, और सब प्रकार के काश्त-कारों के हकों और अधिकारों की रक्षा की गई। इस ऐक्ट में यह व्यवस्था की गई कि जो किसान एक भूमि में १२ वर्ष तक कारन कर ले, उसे मौरूसी अधिकार प्राप्त हो जायें।

औसत मालगुजारी—ब्रिटिश-भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रांतों में सरकार द्वारा लां जानेवाली फ्री एकड़ मालगुजारी की औसत पृथक्-पृथक् है। स्थायी बंदोबस्तवाले प्रांतों में यह औसत १ आना ६ पाई से लेकर १ रु० ५ आने ६ पाई तक, अस्थायी जमींदारी-वाले प्रांतों में ११ आने से लेकर १ रु० १२ आ० ६ पाई तक तथा रयतवारी प्रांतों में १ रु० ५ आ० ॥ लेकर तीन रुपए से भी अधिक है।

कर-संबंधी जॉच-कमेटी ने मालगुजारी के संबंध में जो सिफारिश की है, वह उसकी अन्य करों की सिफारिशों के साथ थगले बंड में दी जायगी।

ज़मीन का मालिक कौन—सरकार या प्रजा ? •—प्राचीन

था। सन् १७१२ ई० में ईस्ट इंडिया-कंपनी ने अपनी कलकत्तेवाली कोटी के पास, ३८ गाँवों की तालुकदारी खरीदने के लिये, एक प्रार्थना-पत्र भेजा था। बादशाह ने कंपनी को प्रजा से गाँव खरीदने की आज्ञा दी थी। पेशवा भी हीमन देकर ही जमीन खरीदते थे।

सन् १८२७ ई० में चंसेल्-डाई कोर्ट के 'कानदा सैंड असेसमेंट' के मुकदमे में जस्टिस वेस्ट्राप और जस्टिस वेस्ट ने इस प्रश्न पर गूँथ विचार कर, हिंदू-धर्म के आधार पर, प्रजा का भूमि-स्वामित्व सिद्ध कर दिया था। प्रिन्सी-पीमिल ने भी इसी का अनुमोदन किया था।

सरकार का भूमि-स्वामित्व कैसे हुआ?—पूर्वाङ्ग विवेचन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि ब्रिगेज-सरकार जमीन की मालिक नहीं मानी जा सकती। तब यह प्रश्न उठता है कि ब्रिगेजों को भूमि-स्वामित्व मिल कैसे गया?

इसके उत्तर में धीजोर्जाजी लिखते हैं—“रहे-गए स्वतंत्र मुसलमान गृहदारों को पदच्युत करके कंपनी ने उन्हें अपने वहाँ मौकर रखा, और उन्हीं के द्वारा राज-काज चलाने लगी। जर्मन का बंदोबस्त भी यही समझकर किया गया कि ब्रिगेज-सरकार ही जमीन की मालिक है। धीरे-धीरे रियल्टी पद्धति प्रचार में आने लगी।”

जमीन से होनेवाली आय में सरकार का अधिकार—अतः, अधिकारियों का कथन है कि भारतवर्ष में भूमि सरकार की है। उसे उस पर स्वाधिकार प्राप्त है। उसने उसे, अपनी ओर से, खपाई का करपायी रूप से, दूसरे व्यक्तियों को दे रखा है। अतएव जमीन की पैदावार से स्वयं काटकर उसे जो लाभ होता है, उसने से सरकार (आधे के लगभग) हिस्सा लेती है।

सिद्धांत तो तो सरकार लाभ का ही हिस्सा लेती है। परंतु व्यवहार में प्रायः ऐसा नहीं होता। सरकार करणव में बहुत हानि ले लेती है। बंदर, अदालत आदि स्थानों में सरकार की एकदम भूमि की

और किसी काम की योग्यता न रहने लगी। अब मिडल-पास की तो बात ही क्या, बहुतों की १०-१५-२० मासिक नहीं पा सकते। कभी-कभी तो ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि ग्रेजुएट केवल ३०-३५ रुपए की मीकरी पाने को मरमते रहे। हमरण रहे, रुपए का मूल्य अब पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गया है। इसलिये यदि मज़दूर पेंशन पहले के समान भी हो, तो भी वह असली पेंशन के विचार से बहुत कम माना जायगा।

मज़दूरी और अन्य पदार्थों में अंतर—मार्ग और पूर्ति के नियम के व्यवहार की दृष्टि से मज़दूरी और अन्य पदार्थों में कुछ अनिवार्य अंतर है। प्रथम तो यही स्पष्ट है कि अन्य पदार्थों की तुलना में मज़दूरी बहुत ही शीघ्र क्षय होनेवाली वस्तु है। भ्रमजीवी का जो समय व्यर्थ चला जाता है, वह खर्चा ही जाता है। इसलिये निर्धन भ्रमजीवी अपने धर्म को जिस क्षीमता पर बने, देना चाहता है। उसकी यह उत्प्रेक्षा मज़दूरी की दर घटाने में सहायक होती है।

पुनः अन्य पदार्थों की पूर्ति की तरह मज़दूरी की पूर्ति में जल्द परिवर्तन नहीं होता। मार्ग होने पर अन्य पदार्थ प्रायः शीघ्र ही बाज़ार में पहुँचाए जा सकते हैं। उनकी दर बहुत समय तक बड़ी दूर नहीं रहती। परंतु भ्रमजीवियों को अपना घर और गाँव (या नगर) तुरंत छोड़ने की इच्छा नहीं होती। उनकी पूर्ति होने में बहुत दिनों भी लग जाता है। इसलिये नए कल-कारखाने खुलने के समय, आरंभ में, कभी-कभी बहुत समय तक मज़दूरी की दर, अन्य पदार्थों की अपेक्षा, बड़ी रहती है। इसी के साथ यह भी बात है कि जो भ्रमजीवी एक बार वहाँ जाकर रहने लग जायेंगे, वे सहसा वहाँ से जाँदेंगे भी नहीं। अतः यदि बाह्य में, किसी घटना-वस्तु, भ्रमजीवियों को मार्ग कम रह जाय, तो वहाँ पूर्ति जल्दी न करने से मज़दूरी की दर का, अन्य पदार्थों की अपेक्षा, बहुत समय तक बड़ी रहना संभव है।

नज़द और असली—बदले बताया जा चुका है कि उत्पादकों को आजकल प्रायः उत्पन्न पदार्थ का कोई हिस्सा न देकर ऐसी रकम दी जाती है, जो उनके हिस्से के पदार्थ की कीमत हो। इस प्रकार धमजीवियों के धम से जो धन पैदा होती है, वही उन्हें नहीं दी जाती। यदि दी जाय, तो बड़ी चमूबिधा हो। मान लो, कोई धमजीवी सोहे या कोयले की खान में काम करता है। यदि उसे उसके धम के बदले सोहा या कोयला ही दिया जाय, तो वह उसका क्या करेगा? उसे इनके बदले अपनी आवश्यकता के पदार्थ—घर-बख आदि—प्राप्त करने होंगे। चौर, यह काम हर समय और हर स्थान में सहज ही नहीं हो सकता। इसलिए आजकल धमजीवियों को उनके धम का प्रतिफल प्रायः रुप-पैसे में चुकाया जाता है। इसे नज़द मजदूरी Money Wages या Nominal Wages कहते हैं। इसके विपरीत यदि धमजीवियों को उनके धम के बदले घर-बख आदि ऐसी चीज़ें दी जायें, जिनकी उन्हें उपभोग के लिये आवश्यकता हो, तो ये चीज़ें उनकी असली मजदूरी हूँ, ऐसा कहा जायगा।

नज़द मजदूरी धमजीवियों की दशा का ठीक अनुमान नहीं होता। उदाहरणार्थ अगर मोहन की रोज़ाना ॥१॥ मिलते हैं, और उसके नगर ॥१॥ गेहूँ का भाव दस सेर का है, तथा सोहन की रोज़ाना ॥२॥ मिलते हैं, और उसके नगर में गेहूँ का भाव दस सेर का है, तो सोहन की नज़द मजदूरी अधिक होने पर भी असली मजदूरी मोहन की ही अधिक मिलनी है। इसी प्रकार अगर दोनों की अपनी विविध आवश्यकताओं का सामान बराबर ही मिले, परंतु मोहन को रहने का मकान आदि मुफ्त मिलना है, अपना काम करने के पैरों के बीच में कपड़ा या मनोरंजन का ऐसा व्यवसाय मिलता है, जो सोहन को नहीं दिया जाता, तो भी मोहन की ही असली मजदूरी अधिक मानी जाएगी। यह स्पष्ट है कि दो धम-

और किसी काम की योग्यता न रहने लगी। अब मिट्टी-पान भी तो बात ही क्या, बहुत ही ० ६०-पान भी ४० ५० ६० मासिक नहीं पा सकते। कमो-कमी तो ऐसे भी उदाहरण मिलें हैं कि ग्रेजुएट केवल ३०-३५ रुपये की माँकरी पाने को मरमने रहें। मरमण रहे, रुपए का मूल्य अब पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गया है। इसलिए यदि मज्झिमा वेतन पहले के समान भी हो, तो भी वह असली वेतन के विचार से बहुत कम माना जाएगा।

मज्झिमा और अन्य पदार्थों में अंतर—मार्ग और पूर्ति के नियम के व्यवहार की दृष्टि से मज्झिमा और अन्य पदार्थों में कुछ अतिव्याप्य अंतर है। प्रथम तो यही स्पष्ट है कि अन्य पदार्थों की तुलना में मज्झिमा बहुत ही शीघ्र खप होनेवाली वस्तु है। भ्रमजीवी का जो समय व्यर्थ जाता जाता है, वह खर्चा ही जाता है। इसलिए निरर्थक भ्रमजीवी अपने धर्म को जिस प्रीति पर बने, खर्च देना चाहता है। उसकी यह उत्प्रेक्षा मज्झिमा की दर घटाने में सहायक होती है।

पुनः अन्य पदार्थों की पूर्ति की तरह मज्झिमा की पूर्ति में जल्द परि-वर्तन नहीं होता। मार्ग होने पर अन्य पदार्थ प्रायः शीघ्र ही बाजार में पहुँचाए जा सकते हैं। उनकी दर बहुत समय तक बढ़ी हुई नहीं रहती। परंतु भ्रमजीवियों को अपना घर और गाँव (या नगर) सुरक्षित छोड़ने की इच्छा नहीं होती। उनकी पूर्ति होने में बहुत बिलंब भी लग जाता है। इसलिए वह कल-कलसाने लड़ने के समय, आरंभ में, कभी-कभी बहुत समय तक मज्झिमा की दर, अन्य स्थलों की अपेक्षा, बढ़ी रहती है। इसी के साथ यह भी जान है कि जो भ्रमजीवी एक घर वहाँ जाकर रहने लग जायेंगे, वे सहसा वहाँ न जायेंगे भी नहीं। अतः यदि वह वे, किसी बटना-बल, भ्रमजीवियों को मार्ग कम रह जाय, तो वहाँ पूर्ति जल्दी न करने से मज्झिमा की दर का, अन्य स्थलों की अपेक्षा, बहुत समय तक बढ़ी रहना संभव है।

है। इस प्रकार काम करनेवालों को निरंतर काम मिलने का निश्चय नहीं होता। बहुधा बेकार भी रहना पड़ता है। इस विचार से वे अधिक वेतन लेते हैं।

व्यवसाय में विश्वसनीयता आदि विशेष गुण की आवश्यकता—डाकूजाने, चेंक या खजाने आदि का काम ऐसा है, जिसमें वद्यपि विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, तथापि विश्वसनीयता आदि गुणों को बहुत ज़रूरत होती है, और ये गुण बहुत कम लोगों में मिलते हैं। • अतः इन कार्यों के करनेवालों में जैसी योग्यता चाहिए, वैसे ही योग्यता के अन्य कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ज़रूरत की आदि को अधिक वेतन मिलता है।

निश्चित वेतन के अनिश्चित कुछ और प्राप्ति की आशा—देहातों की अथवा पुरानों परिवारों से चलनेवाली शहरों की पाठशालाओं में अध्यापक अपेक्षाकृत कम वेतन पर कार्य करते हैं। कारण, उन्हें समय-समय पर विद्यार्थियों के यहाँ से “सीधा” (कुछ आटा, दाल, नमक और घी आदि) तथा मौसमी फल या अन्य कृषि-जन्य पदार्थ मिलते रहते हैं। शहरों की आधुनिक शैली के कारण स्कूलों में मास्टर्स को ऐसी प्राप्ति नहीं होती। इसलिये वे अपेक्षित अधिक वेतन लेते हैं।

पुलिस-विभाग के निम्न पदाधिकारियों (कांस्टेबल आदि) का वेतन वद्यपि प्रायः कम होता है, तथापि कुछ लोग सोचते हैं कि जनसाधारण का हमसे काम पड़ेगा, उन पर हमारा रोब-दाब रहेगा, और समय-समय पर ‘ऊपर की आमदनी’ (जो भेंट या रिश्वत का एक सुंदर नाम है) मिलने के अवसर आते रहेंगे। इसलिये वे बहुधा

• सामान्य देने से विश्वसनीयता हो जाती है; परन्तु जमानन देने की सामर्थ्य भी तो कम ही लोगों में होती है।

से घनिष्ठ संबंध है । सुदीर्घ युद्ध-काल या नए उपनिवेशों को छोड़कर साधारणतः मनुष्यों की संख्या जितनी अधिक होती है, मज़दूरी की दर उतनी ही कम हो जाती है । इसलिये विविध देशों में, समय-समय पर, जन-संख्या कम करने के उपाय किए जाते हैं । अविवाहित रहकर, बड़ी उमर में विवाह करके, जान-बूझकर संतान कम पैदा करके, अथवा कुछ आदमी विदेशों में भेजकर जन-संख्या की वृद्धि रोकी जाती है । शिक्षा, सम्पत्ता और मुल की वृद्धि से संतानोत्पत्ति कम होती है ।

भारतवर्ष की जन-संख्या पर्याप्त है । यद्यपि प्रकृति माँगी और रोगों द्वारा यहाँ संहार का कार्य खूब करती है, तथापि संतानोत्पत्ति भी अधिक होने के कारण यहाँ की जन-संख्या घटती नहीं है । जीविका-प्राप्ति के मार्ग कम और जन-संख्या अधिक होने के कारण, यहाँ मज़दूरी की दर, अन्य देशों की अपेक्षा, बहुत कम है । इसलिये मज़दूरों की दशा सुधारने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि उनकी योग्यता बढ़ाने और उद्योग-धंधों की वृद्धि करने के अतिरिक्त यहाँ की जन-संख्या यथाशक्ति कम की जाय । यह कार्य दो प्रकार से हो सकता है—उपनिवेशों में बसकर, और संतानोत्पत्ति कम करके । परार्थीन होने के कारण यहाँ के आदमी एक बड़ी संख्या में बाहर नहीं जा सकते । फिर जो जाते भी हैं, उनकी हुद्दा देकर दूसरे आदमी हतोत्साह हो जाते हैं । अतएव यहाँ जहाँ तक हो सके, संतानोत्पत्ति कम करने का प्रयत्न होना चाहिए । जो लोग आजीवन प्रत्यक्ष रूढ़िवादी रहकर देश-सेवा में लगे, वे धन्य हैं । इसके अतिरिक्त (क) रोगी और दरिद्र यथासंभव विवाह न करें, (ख) बाल-विवाह, वृद्ध विवाह और बहु-विवाह न हों, (ग) विवाहित स्त्री-पुरुष भी यथाशक्ति संयमी रहें, और उचित समय पर गृहस्थाश्रम त्याग, वानप्रस्थ और संन्यास धारण करें ।

The Human Needs of Labour प्रस्तावित हुई थी। उसमें मान्य होना है कि इंग्लैंड के राउटो महाशय ने यहाँ, यार्कनगर में, नीचे-लिखे नियमों के अनुसार मज़दूरी निश्चित की है*—

(१) यह मान लिया गया है कि प्रत्येक कुटुंब में प्रायः एक पुरुष, एक स्त्री और तीन लड़के रहने हैं।

(२) मज़दूरी इतनी होनी चाहिए कि मज़दूर उसके अपने कुटुंब का स्वाधारण रीति से पालन-पोषण कर सकें। वह स्त्री और बच्चों की मज़दूरी को कुटुंब की आमदनी में शामिल नहीं करते। उनका कहना है कि कुटुंब के पढ़ने पर स्त्रियों को, अपने घरों का काम करने के बाद, न तो समय ही रहता है, और न शक्ति ही। इसलिए उनमें मज़दूरी नहीं कराई जानी चाहिए। और, लड़कों में तो स्कूलों में पढ़ने के अतिरिक्त मज़दूरी कराना बहुत ही अनुचित है।

(३) मज़दूरों का निवास-स्थान काफ़ी हवादार होना चाहिए, और उसमें एक कुटुंब के लिये कम-से-कम एक बड़ा कमरा, तीन सोने के कमरे और एक रसोई-घर होना चाहिए।

(४) मज़दूरों के अन्य आवश्यक खर्चों का भी विचार किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उन्होंने, सन् १९१४ ई० में, एक मज़दूर की मज़दूरी ५ शिलिंग या लगभग तान दर ९ नव आने निश्चित की थी। यदि इन्हीं नियमों के अनुसार भारत के मज़दूर को प्रतिदिन की कम-से-कम मज़दूरी निश्चित की जाय, तो मासूली शहरों में यह वेतन दर से कम न बैठेगा। परंतु वे इससे बहुत कम पाते हैं।

* श्रीशारदा, पृष्ठ १६७८ के आधार पर।

२५ लाख मज़दूरों ने भाग लिया । फिर बहुत-सी हड़तालों की तोड़खोर ही नहीं मिलती । वे जहाँ-की-तहाँ शांत कर दी जाती हैं ।

वास्तव में हड़ताल एक युद्ध-धोपणा है । मज़दूरों को इसे अपना अंतिम अस्त्र समझना चाहिए । यदि बिना काफी विचार किए इसका बार-बार उपयोग किया जाय, तो यह यथेष्ट फलप्रद नहीं होती ।

धर्मजीवी-संघ—भारतवर्ष में पहले एक-एक व्यवसाय करनेवालों की जुहार, बड़ई आदि एक-एक संगठित जाति थी । किंतु अब व्यवसाय और जाति का संबंध शिथिल होता जा रहा है, और स्वतंत्र व्यवसायियों की अपेक्षा कल-कारखानों में काम करनेवाले मज़दूरों की संख्या बढ़ती जा रही है ।

अब क्रमशः मज़दूरों को यह अनुभव होने लगा है कि यदि हम बिना संगठन के अलग-अलग काम करेंगे, और कम मज़दूरी स्वीकार करने के संबंध में आपस में प्रतियोगिता करेंगे, तो कारखाने का मालिक हमारी फूट से लाभ उठावेगा, और कम-से-कम मज़दूरी देगा । हमलिये हमें मिलकर काम करना चाहिए । इस विचार में अब मज़दूर अपना एक संगठित संघ बनाते हैं । संघ ■ सभासद नियमानुसार खंदा देकर एक कोष स्थापित कर लेते हैं । जब कोई सभासद बीमार पड़ जाता है, या किसी दुर्घटना, हड़ताल आदि के कारण काम करने-योग्य नहीं रहता, तो उसे इस कोष से सहायता दी जाती है । यदि किसी के व्यवसायोपयोगी औज़ार आदि नष्ट हो जाते हैं, तो वे तुरीय दिए जाते हैं । यह संघ मज़दूरों के सुधार, शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य आदि के विषय में यथारुचि ध्यान देता रहता है । मज़दूरों की दर उँची रखने के लिये कभी-कभी छोटे-छोटे धर्मजीवी संघ इस बात की कोशिश भी करते हैं कि उनके यहाँ काम करनेवालों की संख्या

बड़ी खूबी से चल रहा है। चंदे का खपना बराबर बमूल किया जाता है। आशा है, थोड़े ही दिनों में वहाँ की मिलों में काम करनेवाले सब लोग संघ में शामिल हो जायेंगे।

पहमदाबाद के अनिश्चित करोंकी और मकूर के रेलवालों तथा शोलापुर के रूंद की मिलवालों का संघ विंगेय ट्रेड्युनीय है।

किन्तु मदरास-बंबई के बाहर मज़दूर-संघों का हुक्मना ग़ौर नहीं रहा। बड़े रेलवे-जाहनों तथा कारख़ानों के बर्मचारियों ने समय-समय पर बड़ी बड़ी हड़तालें कीं, कुछ सफलता भी प्राप्त की, मज़दूर-संघों स्थापित कीं, परंतु संगठन-कार्य विंगेय ब्यर्थी नहीं हुआ।

अंतरराष्ट्रीय मज़दूर-बान प्रो.स.—विश्व-व्यापी संग्राम ने मज़दूर-दल का ग़ौर और भी बढ़ा दिया। संघों के नियमों के अनुसार शासन ने एव अंतरराष्ट्रीय मज़दूर-बान प्रो.स स्थापित की है, जिसमें मज़दूरों की दला सुधारने के उपायों पर विचार होता है। सन् १९२६ ई० तक इस बान प्रो.स के सात अधिवेशन हो चुके हैं। इस बान प्रो.स की प्रबंध-समिति में कुल २४ सदस्य हैं—९ महिलाओं के, ९ मज़दूरों के और दोष १२ सदस्य निरा-निरा देशों की सरकारों द्वारा चुने हुए। इस बारह में आठ का निर्वाचन समय के आठ बड़े बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा और बार का आठ देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। बहुत कुछ प्रयत्न होने के संसार में आठ बड़े-बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की सुखी में भारतवर्ष भी शामिल किया गया है, और अंतरराष्ट्रीय मज़दूर-बान प्रो.स की प्रबंध-समिति में अब हमका भी प्रतिनिधि रहना है। किन्तु वह प्रतिनिधि भारतीय मज़दूरों के हितों का बड़े-बड़े मुद्दे नहीं हो सकता है, जब तक देश-भर के मज़दूर-दल की एक संलग्न संस्था हो।

भाग जाय, और काम न करे, तो वह अभी प्रौजदारी-मिपुदं किया जा सकता है। इसमें मजदूरों की हालत सर्व-सुखियों की-सी हो जाती है। इसे दूर करने का विचार हो रहा है।

संक्षेप में, सरकार मजदूरों के प्रश्न की ओर कुछ ध्यान देने लगी है। प्रत्येक प्रांतिक सरकार की ओर से मजदूरों की अवस्था की जाँच का भी प्रबंध हो रहा है। अब सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिये मजदूरों का संगठन उत्तम जरूरी है, जितना कि पूँजीवाले। परंतु अभी बहुत-सा काम बाकी है।

कांग्रेस का ध्यान—जैसे-जैसे देश में मजदूरों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे यह मालूम होने लगा है कि बिना मजदूरों को स्वराज्य मिले और उनकी आर्थिक दशा सुधरे भारतवर्ष को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। कुछ समय से कांग्रेस में भी इस ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया है।

इसी उद्देश्य से गया की कांग्रेस (१९२२) में यह प्रस्ताव पेश हुआ था—“इस कांग्रेस की यह राय है कि हिंदोस्तान के अमर्जीवियों को—उनके आराम और सुख की वृद्धि के लिये, उनके अधिकारों को रक्षा करने और उनको तथा देश की व्यावसायिक सामग्री को विदेशी पूँजीपतियों द्वारा लूटे जाने से बचाने के लिये—संगठित करना चाहिए। इसलिये यह महासभा अतिव्यक्त भारतीय मजदूर-संघ का, और बहुत सी किसान-सभाओं से इस संबंध में जो कार्य करना आरंभ किया है, उसका स्वागत करती है।”

कांग्रेस द्वारा एक बड़े-से कदम रखा है, जो अमर्जीवियों तथा किसानों के संगठन में सहायता पहुँचावेगी।

विशेष ध्यान—आधुनिक औद्योगिक देशों की तुलना में, भारत-वर्ष में, मजदूरों और किसानों के संगठन बहुत कम है, और उनकी वृद्धि की पूरी आवश्यकता है। परंतु सरल रहे, वे अपने स्व-

ऋण-दाता—भारतवर्ष के बैंकों का वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। अब अन्य ऋण-दाताओं का उल्लेख किया जाता है।

देहातों में बनिप या महाजन कृपि के लिये पूँजी उधार देते हैं। कभी-कभी अनुत्पादक कार्य या फिजूल-श्रुर्ची के वास्ते भी उनसे ऋण लिया जाता है। सरकार भी अकाल के समय बहुधा किसानों को भूमि की उत्पत्ति करने और पशु, बीज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिये, सन् १८८३ और १८८४ ई० के ऐक्ट के अनुसार, 'तन्नावी' देती और इस रूप को अच्छी कसल के अवसर पर वसूल कर लेती है। किंतु राजकर्म-चारियों का समुचित व्यवहार न होने के कारण इस तरीके में विशेष सफलता नहीं हो रही है। फिर रकम भी, कृपकों की मर्यादा और आवश्यकता को देखते हुए, बहुत कम दी जाती है।

शहरों में मेठ-साहूकार जायदाद रेहन करके अथवा जेवर गिरवी रखकर ऋण देते हैं। कभी-कभी वे व्यापारियों और दलकारों की भी सहायता करते हैं।

जमींदार, मंदिरों के महंत या अन्य पेशेवाले लोग भी सूद की ग्रामद्वी के लिये रुपया उधार देते हैं।

शहरों के किनारे ही साहूकार अपने पास रेहन रखी हुई जमीन को मोख लेकर जमींदार बन गए हैं। मुसलमानों के यहाँ ध्याज लेने का, धार्मिक दृष्टि से, निषेध है। परंतु कुछ स्थानों के निम्न श्रेणी के मुसलमान इसमें संकोच नहीं करते। पेशावरी अफगान अधिकतर सीदागरी के साथ सूद-खोरी भी करते रहते हैं।

भारतवर्ष में सूद की दर—यहाँ सूद की दर, पूँजी बहुत कम होने के कारण, अधिक है। साधारण उत्पादक के पास अपनी निजी पूँजी नहीं होती। उसे सूद की मर्यादर दर पर रुपया उधार लेना पड़ता है। अनेक स्थानों में अचछी रूप का साधारण नियम है।

श्रृणु-दाना—भारतवर्ष के धीकों का वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। अब अन्य श्रृणु-दानाओं का उल्लेख किया जाता है।

देवानों में बनिए या महाजन कृषि के लिये पृथी उधार देने हैं। कभी-कभी अनुवादक कार्य या डिग्ल-गुर्ची के बान्ते भी उनमें श्रृणु दिया जाता है। सरकार भी अकाल के समय बहुधा किसानों की भूमि की उत्पत्ति करने और पशु, बीज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करने के लिये, सन् १८८३ और १८८४ ई० के ऐक्ट के अनुसार, 'नव्वाबी' ऐसी और हम १८७० की अच्छी क़सब के अन्तर्गत पर वसूल कर लेती है। किन्तु राजकर्म-चारियों का समुचित व्यवहार न होने के कारण हम मरीजे में विशेष सफलता नहीं हो रही है। फिर राजम भी, कृषकों की संपत्ति और आवश्यकता को देखते हुए, बहुत कम दी जाती है।

गाइनों में गिट-साहूकार जाबदाद रिकन करके अथवा ज़ेवर गिरवी रखकर श्रृणु देने हैं। कभी-कभी वे व्यापारियों और दलबारा की भी सहायता करते हैं।

जमींदार, मंदिरों के मालिक या अन्य पेशवाले लोग भी मृद की आसानी के लिये श्रृणु उधार देने हैं।

गाइनों के कितने ही साहूकार अपने पास रहन रहती हुई ज़मीन को मोख लेकर ज़मींदार बन गए हैं। मुसलमानों के यहाँ इस्लाम धर्म का, धार्मिक दृष्टि से, निषेध है। परंतु कुछ स्थानों के किन्न बेसी के मुसलमान इसमें संकोच नहीं करते। पेशावरी अथवा अधिकांश सादागरी के साथ मृद-खोरी भी करते रहते हैं।

भारतवर्ष में मृद की दर—यहाँ मृद की दर, पृथी बहुत कम होने के कारण, अधिक है। साधारण उपजाऊ के पास अच्छी किस्म की पृथी नहीं होती। उसे मृद की भरकर ज़ा पर खपक उधार लेना पड़ता है। ज़ेबेक स्थानों में अच्छी तरह का साधारण मिट्टा है।

मिश्रित धनवाली समितियों की यथेष्ट वृद्धि से ही इन लोगों की विशेष रक्षा होगी ।

चौथा परिच्छेद

मुनाफ़ा

मुनाफ़ा—किसी उत्पन्न पदार्थ से उसके उत्पादन का सब व्यय—लागत, मजदूरी और सूद—निकाल देने पर जो शेष रहता है, वह मुनाफ़ा है । यह व्यवस्था (Organisation) का प्रतिफल है । व्यवस्था में प्रबंध और साहस, दोनों सम्मिलित हैं, यह पहले बताया जा चुका है । कुछ महाशय 'प्रबंध की कमाई' * का विचार स्वतंत्र रूप से करते हैं । इस दृष्टि में मुनाफ़ा केवल साहस करने या जोखिम उठाने का प्रतिफल रह जाता है । जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, बहुधा कारख़ानेवाले श्रम (एवं उत्पत्ति के अन्य साधनों) का प्रतिफल कम-से-कम देकर बहुत लाभ उठाते हैं । इससे धन-वितरण में धन का बड़ा भाग मुनाफ़े के रूप में रहता है । इसका सामाजिक रिधति पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका विचार अगले परिच्छेद में किया जायगा ।

किन्तु कुछ कामों में मुनाफ़े का सहसा हिसाब नहीं लग सकता ।

* प्रबंधक या मैनेजर का कार्य धनोत्पादन में एक आवश्यक अंग है । वह अन्य श्रमजीवियों के काम की देखभाल करता है । उसका यह कार्य एक श्रमजीवी के कार्य के दग से दूसरे दग का है । इसलिये हम उसकी आय को, जो बहुधा निश्चिन्त होती, और प्रतिमाम मिलती है, वास्तव में मजदूरी नहीं कह सकते । मजदूरी से उसका भेद दिखाने के लिये अर्थ-शास्त्र में उसे एक पृथक् संज्ञा दी जाती है । इसे प्रबंध की कमाई (Earnings of management) कहते हैं ।

मिश्रित धनवाली समितियों की यथेष्ट हृदि हैं ही इन लोगों की विशेष रक्षा होगी ।

चौथा परिच्छेद

मुनाफ़ा

मुनाफ़ा—किसी उद्देश्य पदार्थ में उसके उत्पादन का सब व्यय—
लागत, मजदूरी और मूल—निवाला देने पर जो शेष रहता है, वह
मुनाफ़ा है । यह व्यवस्था (Organisation) का प्रतिपक्ष है ।
व्यवस्था में प्रबंध और साधन, दोनों सम्मिलित हैं, यह पदार्थ
बनाया जा चुका है । कुछ महाशय 'प्रबंध की कमाई' * का विचार
स्वतंत्र रूप से करते हैं । इस दृष्टि में मुनाफ़ा केवल साहस करने का
जोखिम उठाने का प्रतिपक्ष रह जाता है । जैसा कि हम पहले कह
चुके हैं, बहुतों का राजनेवाले धन (एवं उत्पत्ति के अन्य साधनों)
का प्रतिपक्ष कम-से-कम देकर बहुत काम उठाते हैं । हमसे धन-
वितरण में धन का बड़ा भाग मुनाफ़े के रूप में रहता है । इसका
सामाजिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका विचार आगे
परिच्छेद में किया जाएगा ।

नहीं लगा सकता ।

आवश्यक बात है ।

। ठमका २६ करोड़ २६

हज़ारों रुपये उठती

मिलती हैं, वस्तुतः के

। रिश्वत के जिन्हे कर-

इसे प्रबंध की कमाई

है ।

(१) खाने-पीने की चीज़ें मस्ती हो जाना ।

क़ीमत बढ़ने या देश में महँगी होने से मुनाफ़ा हो जाता, यह समझना भूल है । जन-संख्या की वृद्धि अथवा विदेशी माँग के कारण, खेती में पैदा होनेवाले अन्न आदि की खपत बढ़ने से निकृष्ट-तर ज़मीन में खेती करनी पड़ती है । यह बात मज़दूरी आदि का खर्च बढ़ाए बिना नहीं हो सकती, और उत्पादन-व्यय बढ़ने से चीज़ों की क़ीमत का बढ़ना तथा देश में महँगी का होना स्वाभाविक ही है । इससे कारख़ानों को लाभ थोड़ा ही होता है । उनका तो खर्च ही मुश्किल से निकलता है । पुनः जो चीज़ें क़लों की सहायता से बनती हैं, उनकी खपत बढ़ने से मुनाफ़ा अधिक होता है । क्योंकि मात्रा जितना अधिक सैयार होगा, खर्च का अनुपात उतना ही कम पड़ेगा । इस प्रकार क़ीमत कम आने पर भी मुनाफ़ा अधिक हो सकता है ।

(२) मुनाफ़े का समय से भी गहरा संबंध है । मात्र बिककर मुनाफ़ा मिलने में जितना ही कम समय लगेगा, मुनाफ़े की दर उतनी ही अधिक होगी । और, जितना ही समय अधिक लगेगा, मुनाफ़े की दर उतनी ही कम होगी ।

(३) मज़दूरी की दर कम होने से मुनाफ़ा अधिक और मज़दूरी अधिक बढ़ने से मुनाफ़ा कम हो जाता है । कारख़ानेवाले अधिक-से-अधिक मुनाफ़ा चाहते हैं, और मज़दूर अधिक-से-अधिक मज़दूरी । इसलिये उन दोनों में बहुधा पारस्परिक हित-विरोध रहता है । इसका अन्वय प्रसंगानुसार धर्णन किया गया है ।

(४) कारख़ानेवालों की बुद्धिमानी, दूर-देरी और प्रबंध करने की योग्यता पर भी मुनाफ़े की कमी-बेसी बहुत कुछ निर्भर है । देश में अयोग्य कारख़ानेवालों की संख्या अधिक होने से चतुर कारख़ाने के मालिकों के मुनाफ़े की मात्रा बढ़ जाती है । शिक्षा और क़ला-कौशल की वृद्धि के साथ-साथ अयोग्य कारख़ानेवालों की संख्या कम होती

घोड़कर अन्य कोई खामकारी कार्य क्यों नहीं करने लगते ? परंतु उन बेचारों को ऐसा करने की सुविधाएँ हों, तब न। हमारे अनेक किसानों की पूँजी प्रायः वहीं के बराबर होती है। बहुतेरे ऋण-ग्रस्त रहते हैं। शिक्षा का अभाव और संकुचित विचारों तथा अंधविश्वास की प्रधानता उनकी उन्नति में बहुत बाधक होती है। इसलिये वे बेचारे क्यों और बहुधा पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक बिना मुनाफ़े के ही कृषि-कार्य करते रहते हैं, जिसमें उन्हें अपने (अकुशल) श्रम की मामूली-सी मज़दूरी मिल सके। किसी अन्य उद्योग-धंधे के करने की योग्यता न होने के कारण वे और कामों में उतनी भी मज़दूरी पाने की आशा नहीं रखते।

कृषि-साहूकार का मुनाफ़ा—यहाँ महाजन या बलिए किसानों को रुपया उधार देते हैं, और उसके बदले में, फ़सल तैयार होने के समय, बाज़ार से कुछ सस्ते भाव पर, अन्न आदि लेते हैं। इसी में उनका सूद भी आ जाता है। बहुधा ऐसा भी होता है कि ऋण देते समय ही पदार्थ का वह भाव टहर जाता है, जिस पर किसान अपना माछ महाजनों को देते हैं। उक्त मोल लिए हुए पदार्थ को महाजन अपने यहाँ जमा रखते हैं, और फ़सल के पश्चात्, जब उसका भाव बढ़ जाता है, तब धीरे-धीरे बेचते हैं। दरिद्र और अदूरदर्शी किसान अपनी आवश्यकताओं, विवाह-सगाई आदि की रीति-रस्मों और सरकारी लगान आदि चुकाने के लिये, प्रायः इतना माल बेच बाँधते हैं कि कुछ समय के बाद स्वयं उन्हीं को कुछ माल बलिए से, महँगे भाव पर, खरीदना पड़ जाता है। अस्तु। इस ऋण-विक्रय से महाजन मुनाफ़ा लेता है।

शिल्प-साहूकार का मुनाफ़ा—पहले छोटी मात्रा की उत्पत्ति की दशा में बहुत से कारीगर अपनी-अपनी पूँजी में स्वतंत्र कार्य करते थे। उसके वे स्वयं ही निरीक्षक या व्यवस्थापक भी होते थे।

है, जो भारतवर्ष में आना हो, तो अधिकोग मुनाफ़ा इन्हीं मीठगारों को होता है। भारतवर्ष के उद्योगों तथा उपभोगियों को बहुधा बहुत समय पीछे विदेशों के भाव का पना लगता है।

कल-कारखानेवालों का मुनाफ़ा—इनके मुनाफ़े की मात्रा प्रबु होती है। मज़दूर बहुधा इनके हाथ की कटपुतखी ही रहते हैं, और साधारण वेतन पर कार्य करने के लिये बाध्य होते हैं। यदि मज़दूर कमी हदताल भी करें, तो पूँजीपति भुने नहीं मरेंगे, पाटे उनका कारखाना दम-पाँच दिन बंद ही क्यों न रहे। पर येपारे मज़दूर क्या करेंगे? उनके पास इतनी पूँजी कहीं कि दो बार रोज़ भी बैठ सकें, और मज़े में बाल-बच्चों-समेत खाते-पीते रहें। इसलिये उनका कष्ट बहुत अधिक होता है *।

कारखानेवाले अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा सुसंगठित करने के लिये समितियाँ (Millowners Associations) बना लेते हैं। तब वे और भी अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। वे सदैव यही सोचा करते हैं कि अधिकाधिक मुनाफ़ा पावें, और धनी बनें।

पुस्तक-प्रकाशकों का मुनाफ़ा—अंगरेज़ी तथा देशी भाषाओं की पुस्तकें प्रकाशित करनेवाले महाशय भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक मुख्य नगर में हैं। इनकी संख्या तथा इनके द्वारा साहित्य का प्रचार बढ़ रहा है, यह देशोन्नति का चिह्न है। परंतु हमें यहाँ इनकी मिलने-वाले मुनाफ़े पर विचार करना है। प्रायः लेखक बहुत निर्धनता का जीवन व्यतीत करनेवाले होते हैं। वे अपने धर्म का प्रतिफल पाने

* कमी-कमी ऐसा भी होता है कि व्यवसाय-पति (कारखानों के फाटक में ताला लगाकर) मज़दूरों का थाना रोक देते हैं, जिससे मज़दूरों पर उनका प्रभुत्व बना रहे, और वे अधिक मज़दूरी या अवकाश आदि न माँगे। इसे द्वारावरोध (Lock out) कहते हैं।

पाँचवाँ परिच्छेद सामाजिक स्थिति

धन-वितरण और समाज—समाज की प्रारंभिक अवस्था में लोगों को स्वामित्व या मिश्रकियत का विचार नहीं था । किसी को किसी चीज़ के संबंध में अपने और पराए का कुछ ध्यान भी न था । उस समय समानता का विशिष्ट युग था , न कोई ज़मींदार था, न महाजन, न मज़दूर । राजा और प्रजा का भी भेद-भाव न था । किंतु मर्यादा की वृद्धि के साथ-साथ स्वामित्व का भाव भी धीरे-धीरे समाज में बढ़ने लगा । जब संपत्ति का भी वितरण होने लगा ।

वर्तमान अवस्था में जिसकी ज़मीन है, वही यदि पूँजी भी लगावे, और मिहनत भी करे, तो धनोत्पत्ति में इन तीनों साधनों का प्रतिकूल पाने का वही एकमात्र अधिकारी हो । हाँ, सरकार कुछ कर अवश्य लेगी । भारतवर्ष में तो सरकार ने ज़मीन पर अपना ही अधिकार समझ रक्खा है । यदि यहाँ कोई आदमी ज़मीन पर अपनी पूँजी और मिहनत भी लगावे, तो भी सरकार उत्पन्न धन में से एक अच्छा हिस्सा लगान के नाम वें ले ही लेगी ।

धन का असमान वितरण और उसका परिणाम—इस समय भिन्न-भिन्न देशों में एक ओर तो मुट्ठी-भर आदमी ज़ख़्ख़ती हो गए हैं, जिन्हें दिन-रात वही चिंता रहती है कि इतने धन का क्या करें । दूसरी ओर उनके असंख्य देशवासी भाई, घोर परिश्रम करने पर भी, पेट-भर भोजन थयवा शरीर-रक्षा के लिये आवश्यक वस्त्र तक नहीं पाते । इसीलिये तो संसार में तरह-तरह के आंदोलन हो रहे हैं । इंग्लैंड में मज़दूर-दल का आंदोलन प्रसिद्ध ही है । जर्मनी में उसे साम्यवाद का नाम दिया गया है । रूस में उसे बोल्शेविज़्म कहा जाता है । भारतवर्ष में किसान बहुधा ज़मींदार,

व्यवसाय में सफलता होती है। फिर भी मैं भूखा मरता हूँ, मेरी मानसिक उन्नति नहीं होने पाती।

(४) मैं भी अपने देश का वैसा ही नागरिक हूँ, जैसा पूँजी-पति। पूँजीपति राज्य को ऐसे कार्य में क्यों सहायता देना है, जिससे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मारा जाता है। क्या मैं देश के धनी-त्पादन में दिन-रात पसीना नहीं बहाता ?”

उधर पूँजीपति कहता है—

“मेरे कारखाने में शारीरिक कार्य सबने घटिया दर्जे का काम है, और मैं उसका वैसा ही प्रतिफल (मजदूरी) दे देता हूँ। मजदूरों की सहायता से बने हुए माल के खिये उपयुक्त मंडी में हो सलाह करके उसे वहाँ ले जाता हूँ। (पूँजीपति यहाँ यह भूल जाता है कि माल ले जाने के खिये रेल, जहाज़ आदि सब साधन मजदूरों की सहकारिता से ही चलते हैं) मैं वैज्ञानिकों को अपने काम में लगाता हूँ। मैं पहले मजदूरों की मजदूरी घटाता हूँ, उसके बाद नफ़ा मेरी जेब में आती है। बाज़ार के उतार-चढ़ाव, संसार की बड़ी घटनाएँ, स्वदेश या विदेश की माँग, नए फैशन और नई आवश्यकताएँ आदि बातों से मुझे मुनाफ़ा मिलता है। इससे मजदूर कुछ नहीं करते। इसलिये उन्हें मेरे लाभ का कोई हिस्सा पाने का क्या अधिकार ? फिर भी मैं समय-समय पर उनकी मजदूरी बढ़ाना रहता हूँ। लेकिन उनकी माँग हृद से ज्यादा बड़ी हुई है। मैं जितना ही ज्यादा दबता हूँ, उतना ही वे हड़ताल की धमकी अधिक देते हैं। मजदूरों के नेता शांति का विचार करें। उनकी उचित शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने को मैं सदा तैयार हूँ। लेकिन वे क्या ही मुझसे द्रोह करें, तो इसका क्या इलाज ?”

और, अब राज्य कहता है—

“मजदूरों के काम करने के घंटे हमने कम कर दिए हैं। उनके

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के बल-कारणों में। दूसरा कारण यह मालूम पड़ता है कि पहले पूँजीपतियों और निरुद्धों की एक दूसरे के विरुद्ध दलबंदी नहीं थी, बरन् एक बड़ी गृहयुद्धों के सदस्यों की भाँति वे आपस में यथेष्ट सहानुभूति और प्रेम रखते थे। धनिकों को अपने धन का अभिमान नहीं था। वे अपने धन की सर्वसाधारण के उपयोग में लगाते थे। उनके बगीचे, पुस्तकालय, चायबग़, धर्म-शास्त्र आदि सबके लिये खुली थीं।

भारतवर्ष की वर्ण-व्यवस्था—इस संबंध में भारतवर्ष की वर्ण-व्यवस्था विरोध विचारणीय है। प्राचीन समय में यहाँ बुद्धिमान् मनुष्यों (ब्राह्मणों) का, धन-हीन होने पर भी, यथेष्ट सम्मान था। उन्हीं का परामर्श लेकर राजा भी अपना कार्य करता था। क्षत्रिय धनवान् न होने पर भी शक्तिशाली थे, और वे उसी में सुखी थे। वैश्य धनवान् होते थे, परन्तु जब वे अपने धन से औरों का उपकार करते रहते थे, तो किसी की उनसे ईर्ष्या क्यों होती? शूद्र शारीरिक श्रम करते थे, परन्तु अपने भोजन-वस्त्र आदि के लिये आज्ञाज्ञ की तरह तारसते न रहकर पूर्ण रूप से निश्चित रहते थे। ऐसी अवस्था में समाज के एक वर्ग को दूसरे से स्वर्दा नहीं हो सकती थी।

पर अब भारतवर्ष का प्राचीन आदर्श लुप्तप्राय हो गया है। तो भी आधुनिक सभ्यता की शकाधीन में आकर हमें प्राचीन आदर्श के सदगुण न भुलाने चाहिए। आधुनिक सभ्यता में भौतिकवाद (Materialism) में धनी मनुष्य दूसरों को हिताहित की चिन्ता नहीं करता। और, सब लक्ष्मियों की बेटब पूजा करने को तत्पर है। इसी में पारस्परिक स्वर्दा, ईर्ष्या और कलह है। इसीलिये बहुत ही तत्त्ववेत्ता इस सभ्यता का मूलोच्छेद करने की चेष्टा कर रहे हैं।

धन-वितरण-पद्धति में सुधार—निस्संदेह उत्पन्न धन में उसके विविध उत्पादकों को यथाशक्ति समानाधिकार मिलने से

सकना । संभवतः इसका यह प्रभाव घटाय होगा कि फिर लोगों में ज्यादा धन-संग्रह करने और बड़े-बड़े पूजोपति बनने की अभिलाषा बढ हो जायगी, और समाज में, धन-वितरण की दृष्टि से, कुछ अधिक समानता आ जायगी । इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि भारतवर्ष के प्राचीन गृह-शिवर के आदर्श से इस समय किस प्रकार और किन्ना लाभ उठाया जा सकता है ।

सातवाँ खंड



पहला परिच्छेद स्थानीय राजस्व

प्राग्गणन—हम पहले चंड में कह आए हैं कि आधुनिक देशों में राजस्व का अग्नित्व अभिवार्य है। यदि ठीक राजस्व-प्रबंध न हुआ, तो जान-माल का हार बना रहने के कारण लोग बहुत कम धन पैदा करेंगे, और जो कुछ करेंगे भी, उसे सीमा उपभोग वर हाखने अधवा दियाकर रखने का प्रयत्न करेंगे। देश की आर्थिक दशा चम्पी नहीं रहेगी। इसीलिये राजस्व-प्रबंध की प्रत्येक देश में आवश्यकता होती है।

देश-काल की परिस्थिति के अनुसार राजस्व को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इनमें बहुत-सा खपता भी प्रचल होता है। इसे राजस्व तरह-तरह के ढंग लगाकर समूह करता है।

भारतवर्ष में राजस्व ० से संबंध रखनेवाले तीन अधिकारी हैं—

- (१) स्थानीय स्वराज्य-अंशधारि,
- (२) प्रांतीय सरकार,
- (३) केंद्रीय सरकार।

ये सब मिलकर प्रतिवर्ष महा हो सौ करोड़ रुपए से अधिक खर्च करती हैं, और लगभग इनकी ही रकम विविध ढंगों में वसूल करती हैं। हमसे भारतीय राजस्व का महत्व अच्छी भाँति समझ में आ

० राजस्व का कार्य राजस्व या राजस्व का आय-व्यय है। कुछ महानगर राजस्व से विशेषतः आय का ही अधिप्राप्त होते हैं। पानु इस हिसाब विशेषतः में आय और व्यय, दोनों का ही विचार आवश्यक स्थानों पर रखने से सम्भव है।—नेहरू।

कार्य भी म्युनिसिपैलिटियों के सिपुर्दे था । पर अब यह उनसे वापस ले लिया गया है ।

कलकत्ता, मदरास, बंबई और रंगून की म्युनिसिपैलिटियों में म्युनिसिपल-कारपोरेशन अथवा केवल कारपोरेशन कहते हैं । म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों का काम लगभग एक ही प्रकार है । परंतु कारपोरेशनों का कार्य-क्षेत्र विस्तृत है ।

म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों की आय के साधन-म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों की आय के मुख्य द्वार निम्नलिखित हैं—

(क) चूंगी (अधिकतर उत्तर-भारत, बंबई और मध्यप्रदेश में)—यह म्युनिसिपैलिटी की सीमा के अंदर आनेवाले माल तथा जानवरों पर लगती है ।

(ख) मकान और ज़मीन पर टैक्स (मदरास, बंबई, बंगाल, मध्य-प्रान्त आदि में)—यह साक्षान्त किराए पर मा।) की सदी अधिक नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) व्यापार-धंधों पर टैक्स (अधिकतर मदरास और संयुक्त प्रान्त में) ।

(घ) हंसियत, जायजद या जानवरों

(ङ) यात्री-कर (तीर्थ-स्थानों

(च) सबकों

आसाम

मोटर त

कसाई

हो जाता है। उदाहरणार्थ, बंबई शहर को छोड़कर बंबई-गोन में कुल प्रार्थ का २१ प्री सैकड़ा से अधिक तथा मध्यप्रान्त-बहार में १२ प्री सैकड़ा से अधिक शिक्षा में व्यय होता है।

यूनिवर्सिटियों और कारपोरेशनों के क्षेत्र की जनता और उस पर कर—भाग के कोष्टक से यह मालूम हो जायगा कि भिन्न भिन्न प्रांतों की यूनिवर्सिटियों और कारपोरेशनों की सीमा के भीतर किन्ती जनता रहती है, और उस पर आदर्श पाँचे किन्ता कर लगता है—

यूनिवर्सिटियों और कारपोरेशन	यूनिवर्सिटल सीमा में जन संख्या	यूनिवर्सिटल सीमा में सीटों की संख्या	प्रत्येक आदर्श पर यूनिवर्सिटल कर की सीमा
			र० आ० पा०
मैसोरेमी नगर			
कलकत्ता	६,०३,१०३	१	१२ ० ६
बंबई	६,०६,४४२	१	१४ ० ६
मद्रास	२,१८,६६०	१	२ १० ४
रांगून	२,८४,६३४	१	१३ ० ६
जिला-यूनिवर्सिटियों			
बंगाल	२०,४१,२११	११२	२ ११ ०
बिहार-उर्दूमा	१२,०४,६६८	२८	१ ६ ४
छत्ताग	१,६०,३००	१२	२ २ ६
बैरु और सिंध	२४,६०,८२४	१२०	२ १३ ४
मद्रास	२४,८२,०००	८१	२ ० ३
संयुक्तप्रान्त	२६,८४,००३	८४	२ २ ६
पंजाब	१६,२६,२०६	१०१	४ २ ८
एरिचमीनार-सीमा-गोन	१,४१,६२८	६	६ २ ६
मध्यप्रान्त बहार	२,२०,१०६	६०	२ १२ १
मद्रास	०,४०,६०२	४०	२ १३ ०

लेखक	प्राप्त (रुप)	प्राप्त (रुप)	प्राप्त (रुप)
संस्कृत	१,६०,८१,०००	१,६०,००,०००	१६,१८,००,०००
संस्कृत	१,६१,१८,०००	१,०१,६६,०००	११,००,००,०००
संस्कृत	११,८४,०००	१८,००,०००	१४,००,००,०००
संस्कृत	००,४८,०००	०१,००,०००	१,००,००,००,०००
संस्कृत	०१,१०,०००	००,००,०००	१,००,००,००,०००
संस्कृत	०१,१०,०००	००,००,०००	१,००,००,००,०००

ईप्रुपमेंट-ट्रस्ट—नगर की सज्जि के लिये कलकत्ता, बंगाल
कलकत्ता आदि शहरों में ईप्रुपमेंट-ट्रस्टों की योजना हुई है। संयुक्त
सदस्यों को चोरी करना, घनी बगियों की हवादार बनाना, शरीर
और मजदूरों के लिये मकान की व्यवस्था करना आदि इन ट्रस्टों
का कर्तव्य है। कलकत्ते का यह ट्रस्ट सन् १९१२ ई० में बना है।
इसमें दस सभासद हैं। सभापति सरकार नियुक्त करती है।
ट्रस्ट का वेतन-भोगी कर्मचारी है, और अपने पद के कारण ट्रस्ट
या संघ होता है। ट्रस्ट आचरणानुसार सरकार का अर्थ होता है।
शरीर काय के अर्थ साधन ये हैं—ज्यावर जायदाद की विधि
अथवा और दान-यत्र पर २) मकदों की ग्रांथ-द्यूटी, ३० मील तक
का कलकत्ते में आनेवाले मुसाफिरों पर एक आना टैक्स, कच्चे जूट का
४०० पीर की प्रीमियम पर दो आने धुंगी, एक्साइज द्यूटी तथा
कलकत्ता-कारपोरेशन के करों का २) मकदों और देह लाख रु
वापिस सरकारी सहायता।

लगान के साथ ही, प्रायः एक आना की रूप के हिसाब से वसूल करके, इन थोड़ों को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिये सरकार भी कुछ रकम देती है। आय के अन्य द्वार तालाब, घाट और सड़क के महमूल हैं। सब-डिविजनल थोड़ों की आय का कोई स्वतंत्र द्वार नहीं। उन्हें समय-समय पर जिला-थोड़ों से ही कुछ मिल जाता है। जिला-थोड़ों की समस्त आय लगभग १० करोड़ रुपए है। कहना न होगा कि यह आय ग्रामों की जन संख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए बहुत कम है। यही कारण है कि हमारे अधिकांश जन-समाज को अभी तक इन थोड़ों से थोड़ा लाभ नहीं हो पाया है।

कुल जिला-थोड़ों की आय तथा व्यय प्रतिवर्ष लगभग १० करोड़ रुपए होता है।

पंचायतें •—पंचायतों की स्थापना और उन्नति का कार्य, अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार करने के लिये, प्रांतिक सरकारों पर छोड़ा गया है। भारत-सरकार ने उनसे सन् १९१८ ई० के एक मंत्रालय में इसे बढ़ाने का अनुरोध किया था। प्रायः महदेरा और मध्य-प्रांत में यह कार्य बहुत धयनन दशा में, और पंजाब, मद्रास, बिहार-उड़ीसा, आसाम तथा मध्यप्रान्त में यह अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में है।

प्रत्येक पंचायत का एक ग्राम-कोष होता है। उसमें मुद्राओं की प्रीति, जुर्माना और सरकार से दी हुई रकम रहती है। प्रायः पंचायतें कलेक्टर की अनुमति से ग्राम-कोष की कोई रकम, धरने क्षेत्र की उन्नति करने या उसके निवासियों को सुविधा पहुँचाने के लिये, व्यर्थ कर सकती है।

• ऐसक की 'भारतीय राजस्व' के आधार पर।

लगाव के साथ ही, प्रायः एक आना प्री रूप के हिसाब से वसूल करके, इन बोर्डों को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिये सरकार भी कुछ रकम देती है। आय के अन्ध द्वार तालाब घाट और सड़क के महमूल हैं। सब-दिविजनल बोर्डों की आय का कोई स्वतंत्र द्वार नहीं। उन्हें समय-समय पर जिला-बोर्डों से ही कुछ मिल जाता है। जिला-बोर्डों की समस्त आय लगभग १० करोड़ रुपए है। कहना न होगा कि यह आय ग्रामों की जन संख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए बहुत कम है। यही कारण है कि हमारे अधिकांश जन-समाज को अभी तक इन बोर्डों से बड़े लाभ नहीं हो पाया है।

कुल जिला-बोर्डों की आय तथा व्यय प्रतिवर्ष लगभग १० करोड़ रुपए होता है।

पंचायतें •—पंचायतों की स्थापना और उन्नति का कार्य, अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार करने के लिये, प्रांतिक सरकारों पर छोड़ा गया है। भारत-सरकार ने उनसे सन् १९१८ ई० के एक मंत्रालय में इसे बढ़ाने का अनुरोध किया था। प्रायः मल्लदेरा और मध्य-प्रांत में यह कार्य बहुत अवनत दशा में, और पंजाब, मद्रास, बिहार-उड़ीसा, आसाम तथा संयुक्तप्रांत में यह अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में है।

प्रत्येक पंचायत का एक ग्राम-कोष होता है। उसमें मुहुरमों की प्रीति, जुर्माना और सरकार से दी हुई रकम रहती है। प्रायः पंचायतें कलेक्टर की अनुमति से ग्राम-कोष की कोई रकम, अपने क्षेत्र की उन्नति करने या उसके निवासियों को सुविधा पहुँचाने के लिये, व्यर्थ कर सकती हैं।

अच्छ-मिन्न प्राँतों से कुछ अंगर होने हुए हैं। निम्न छिद्रित मूल्य विषय अधिकांश में रहित हैं—

१. आचराजी और महर
२. जमीन की आयलगाहरी
३. अक्षय-दीर्घाओं की महराणा
४. अक्षय-विमान और अक्षय-गुट्टी
५. अक्षय-गुट्टी विषय
६. महराणा-गुट्टी और अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
७. अक्षय-गुट्टी और अक्षय-गुट्टी
८. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
९. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
१०. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
११. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण

१०. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण

११. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण

अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण

१. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
२. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
३. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
४. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
५. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
६. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
७. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
८. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
९. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
१०. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण
११. अक्षय-गुट्टी का नियन्त्रण

प्रांतीय और केंद्रीय राजस्व

१९२५-२६ का अनुमानित व्यय (लाख रुपयों में)			
संख्या	मद	केंद्रीय सरकार	प्रांतीय सरकार
१	कर समूल करने का खर्च	५,२६	१०,६०
२	रेल	२८,६६	
३	आवपारी	१८	४,७६
४	अर्थ का सुद	१८,१८	५,६५
५	शासन		१०,७८
६	न्याय-मुक़ीस और जेल		२२,०२
७	शिक्षा		१०,६४
८	स्वास्थ्य और चिकित्सा	१०,६८	२,०५
९	कृषि और उद्योग		२,७०
१०	अन्य विभाग		२६
११	सिविल निर्माण-कार्य	१,६८	८,०६
१२	सैनिक व्यय	६०,२६	
१३	विविध	४,७२	७,७३
१४	केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों की परस्पर में देनी		६,४८
	योग	१,२६,६५	६३,५८

खर्च की मदों का ब्योरा—नं० १ में कर समूल करने के खर्चों में आयात-निर्यात-कर, आय-कर, माखगुजारी, अदालतों, जंगल, रजिस्ट्री, अक्रीम, नमक और आवकारी आदि विभागों के कर्मचारियों के वेतन आदि के अतिरिक्त अक्रीम और नमक करने का खर्च भी सम्मिलित है।

२ और ३ नंबर के खर्च की मदों में इन मदों में खास पूंजी का सुद भी है।

प्रान्तीय और केंद्रीय राजस्व

१९०१-२६ की अनुमानित आय (लाख रुपये में)			
संख्या	मद	केंद्रीय सरकार	प्रान्तीय
१	आयात-निर्यात-कर	४६, ३८	
२	आय-कर	१७, ३८	२
३	नमक	६, ६८	
४	अन्नीस	३, ८६	
५	मालगुजारी		३६, ३
६	आयकारी		१६, ७
७	स्टॉप		१२, ६
८	रजिस्ट्री		१, २
९	अन्य आय	२, २३	३
१०	रेल	३३, ८६	
११	आलपाजी	१०	६, १
१२	जंगल		५, ३
१३	टार और तार	६८	
१४	मृद की आय	३, ६०	५, १
१५	सिविल शासन	७३	३, ३
१६	मुद्रा-टकसाल और विनि- मय	४, ०८	
१७	सिविल निर्माण-कार्य	१०	६
१८	सैनिक आय	४, ०१	
१९	विविध	८२	१, ६
२०	प्रान्तीय सरकारों से लेनो	६, ४८	
योग		१३०, ६३	६०,

उसमें सिर्फ १॥ करोड़ रुपए का इर्ब घटाने की सिफारिश की गई है। उसका ज्योरा इस प्रकार है—

सेना में	१०॥	करोड़ रुपए
रेल में	४॥	"
डाक और तार में	१॥	"
अन्य सिविल खर्चों में	३	"
योग	१६॥	करोड़ रुपए

किन्तु दरिद्र भारत में इतना अधिक व्यय हो रहा है कि उपर्युक्त किरायात बहुत कम है। कम-से-कम इससे तिगुनी किरायात करने की आवश्यकता थी। परंतु विदेशी सरकार को इस बात की चिंता ही नहीं कि दरिद्र भारत टैक्सों के भार से कितना दबा जा रहा है। भरतु, किरायात-कमेटी का कार्य संतोष-प्रद नहीं कहा जा सकता।

सरकारी ध्रुण—जब सरकार इतना अधिक इर्ब करती है कि करों के बढ़ाने पर भी धधेए आय नहीं होती, तब उसे खर्च खेना पड़ता है। इसी कारण भारतीय शासन-व्यय बेहद बढ़ता गया है। पहले तो करों की मात्रा बढ़ाकर काम चलाया गया, साथ-ही-साथ खर्च की मात्रा भी क्रमशः बढ़ती गई। इधर, पिछले कुछ वर्षों से, इस साल आय में व्यय अधिक हुआ। आय की अपेक्षा १९१८-१९ में ६ करोड़, १९१९-२० में २४ करोड़, १९२०-२१ में २६ करोड़, १९२१-२२ में ६८ करोड़ और १९२२-२३ में ६ करोड़ रुपए का अधिक व्यय हुआ। अतएव खर्च बढ़ता ही गया। बांधा रेंजों और नहरों के खिये भी खर्च लिपा जाता है। महापुरु और उसके पूर्व भी कई एक छाड़ाईयों के समय भारत की सीमा के बाहर भी, भारत के विभिन्न (१), प्रर्ष किया गया। हम सब बातों से खर्च की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है।

आगे जितने कोटक से यह बिदिन हो जगणा कि सरकार पर किस-किस प्रकार का किनुना-कितना खर्च है—

भारतवर्ष के मिर से यह आण-भार कब दूर होगा ? कम-से-कम यह और नो न बड़े । पर यह तभी हो सकता है, जब यहाँ शासन-व्यय—और विशेष कर सैनिक व्यय—कम किया जाय । क्या सरकार इसके लिये तैयार होगी ?

फर-जॉय-समिति—सन् १९२४ ई० में सर चार्ल्स टॉड हंटर के सभापतिपद में एक समिति भारत की कर-संबंधी विविध बातों पर विचार करने के लिये पैठाई गई थी । उसमें ६ सदस्य थे, जिनमें चार भारतीय थे ।

सन् १९२६ के आरंभ में इस समिति की भी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई । इसकी मुख्य-मुख्य निष्कारिमें निम्न लिखित हैं—

(१) माखगुजारी जमान के धारतविक खगान के २५ प्री सैकड़ा से अधिक न हो, और वास्तविक खगान का हिसाब खगाने में उत्पादन-व्यय, किमान और उसके कुटुंब के श्रम का प्रतिफल तथा उसके मुनाफे का पूरा ध्यान रक्खा जाना चाहिए ।

(२) जिला-बोर्डों के लिये प्रांतिक सरकारें, माखगुजारी के २५ प्री सैकड़े तक स्थानीय कर (Local rates) खगावें (आजकल भिन्न-भिन्न प्रांतों में प्रायः माखगुजारी का २५ प्री सैकड़े इस कर के रूप में लिया जाता है) ।

(३) शराबों पर आयात-कर बढ़ाया जाना चाहिए ।

(४) शकर, उद्योग-धंधों के लिये कच्चे पदार्थों और उत्पादन के साधनों पर आयात-कर कम करना चाहिए ।

आयात-करों की दरों के संबंध में समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए । इस समय इस काम के लिये एक समिति तुरत नियुक्त की जानी चाहिए ।

(५) (क) कच्चे समुद्र के संबंध का निर्वाण कर हटा देना चाहिए ।

अथवा । सेना और शासन आदि का जो भयंकर खर्च हमारे ऊपर लाद दिया जाय, उसे अस्वीकार करने का हममें बल नहीं । गौड-स्टैंड-कोप के करोड़ों रुपयों के यहाँ रहने और उपयोग करने का हमें कोई हक नहीं । इस कारण अमीर देश पढ़ने पर भी देश दरिद्र और दुखी है । वास्तव में उसे आर्थिक स्वराज्य की बड़ी आवश्यकता है । इसलिये समस्त भारत-संतान को मिलकर इसकी शीघ्र प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए ।



शब्दावली

लेखक का वक्तव्य

अर्थ-शास्त्र-शब्दावली का तैयार करना बड़ा कठिन, किंतु महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है । कारण, यदि आवश्यक शब्द-आंदार हो, तो अर्थ-शास्त्र के लेखक का काम बहुत सुगम हो जाय । गत ११ वर्षों से, जब से हम राजनीतिक, शिक्षा-संबंधी और आर्थिक विषयों को पुस्तकों लिख रहे हैं, हम इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं । इस पुस्तक को लिखते समय हमने यह विचार किया था कि एक वृहत् अर्थ-शास्त्र-शब्दावली (हिंदी से अंगरेजी और अंगरेजी से हिंदी) तैयार करके पुस्तकाकार प्रकाशित करें । इसके लिये बहुत कुछ परिश्रम भी किया, और अब तक प्रकाशित विविध कोषों की एवं कई विद्वान् मित्रों की सहायता भी ली । पर उसमें अभी और परिश्रम तथा अन्य विद्वानों के परामर्श की आवश्यकता है । अतएव यहाँ उन्हीं थोड़े-से अंगरेजी-शब्दों के पर्यायवाची हिंदी-शब्द दिए हैं, जो इस पुस्तक में विशेष रूप से आए हैं । इस कार्य में नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी के हिंदी वैज्ञानिक कोष और इन्डियन इकॉनोमिक एसोसिएशन की हिंदी नाम-क्लेयर सब-कमेटी की एक छपी हुई सूची में सहायता ली गई है । इसके अतिरिक्त निम्न-लिखित सज्जनों ने भी इस कार्य में विशेष सहायता दी है —

१. श्रीरामजी आनंदभिक्षुजी सरस्वती, डॉनरेरी जनरल मैनेजर, प्रेम महाविद्यालय, वृंदावन ।

२. श्री० चिदंजीलाजी माहेंदरो बी० ए०, कासगंज ।

३. श्री० दयारामजी दुबे एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, मंत्री, भारतीय अर्थ-शास्त्र-परिषद्, खलनड ।

शब्दावली

Accounts.	हिसाब, लेखा
Administration.	शासन
Alternative demand.	वैकल्पिक माँग
Amalgamation of banks.	बैंकों का एकीकरण
Artificial coin.	बनावटी सिक्का
Auxiliary capital.	महायक पूँजी
Balance of trade.	व्यापार की बाज़ी
Barter.	बदल-बदल
Bimetallism.	द्विधातु-चक्रन-य इति
Broker.	दलाल
Cadastral survey.	जिम्माशर पैमायश
Capitalist.	पूँजीपति
Central Government.	केंद्रीय सरकार
Charter.	अधिकार-पत्र
Circulating Capital.	चल-पूँजी
Circulation.	चलन
Classification.	वर्गीकरण
Cognisability.	पहचान का गुण
Comfort,—Articles of.	आराम की चीज़ें
Commerce.	वाणिज्य
Commodity.	वस्तु या वस्तु
Communication.	सम्पर्क

Economic.	आर्थिक
Economics.	अर्थ-शास्त्र
Efficient labour.	कुशल श्रम
Elasticity of demand.	माँग की लोच, माँग की घट-बढ़
Enterprise.	साहस
Enterprising.	साहसी, जोखिम का जिम्मा लेने-वाला
Exchange.	विनिमय
Excise duties.	आयकारी का कर, देरी माख पर कर
Existence,—Necessaries of.	जीवन-रक्षक पदार्थ
Experiment.	प्रयोग
Expert.	विशेषज्ञ
Exports.	निर्यात
Factor of production.	उत्पत्ति के अंग
Factory.	कारखाना, फैक्टरी
Fiscal.	बोच-सीधी, आर्थिक
Fixed Capital.	निश्चल पूँजी
Forced labour.	देगार
Free trade.	मुक्तदर-व्यापार
Fund,—Reserve.	बचत-कोष, रिजर्व-फंड
Gold Exchange standard.	स्वर्ण-विनिमय-रिजर्व, स्वर्ण-विनिमय-मुद्रा-व्यवस्थापकी
Gold standard, reserve.	मुद्रा-रक्षार्ण-आम-कोष, स्वर्ण-रिजर्व-कोष

arket.	बाज़ार
arket,—Occasional.	हाट, पैठ
,—Money.	मरात्रा
aximum.	अधिकतम
ans of subsistence.	निर्वाह के साधन
edium of exchange.	विनिमय का माध्यम
ddle-man.	दलाल, मध्यम
neral product.	व्यभिक्त पदार्थ
inimum.	न्यूनतम
ntage.	टक्काजी महसूल
int par.	टक्काजी दर
oney.	मुद्रा, रुपया-पैसा
ono-Metallism.	एकधातुवाद
orality.	सदाचार
ation.	राइ
et income	जमी आग
et rent.	आधिक किराया
o-rent-land.	बे-किराया जमीन
ccupancy right.	मौसमी हक
rganisation.	संगठन
aper Currency.	कगरी मुद्रा
aper money.	कगरी रुपया
asant proprietor.	सुर-कारनकार
ermanent settlement.	स्थायी बंटवारा
opulation,—Growth of.	जन-संख्या-वृद्धि

Market.	बाजार
Market,—Occasional.	हाट, पेंट
" ,—Money.	सराफा
Maximum.	अधिकतम
Means of subsistence.	मिथाई के साधन
Medium of exchange.	विनिमय का साधन
Middle-man.	दूतालय, मध्यस्थ
Mineral product.	खनिज उत्पाद
Minimum.	अल्पतम
Mintage.	हवसारी का मूल्य
Mint par.	हवसारी दर
Money.	मुद्रा, रुपया-दीन
Mono-Metallism.	एकधातुवाद
Morality.	सदाचार
Nation.	राष्ट्र
Net income	जमी आम्द
Net rent.	आधिक अमान
No-rent-land.	बे-अमान जमीन
Occupancy right.	सीकरी हक
Organisation.	संगठन
Paper Currency.	कागजी मुद्रा
Paper money.	कागजी रुपया
Peasant proprietor.	सुर-कामकाम
Permanent settlement.	स्थायी बंदेबस्त
Population,—Growth of.	जन-वृद्धि-वृद्धि

